राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका

मूल्य ₹50/-

तेजस बिन्दु

वर्ष–02, अंक–12, जुलाई–2025

RNI No.: UPHIN/2023/87359

देश के लाल
लालू प्रसाद यादव

तेजस INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES

LATERA, DUMARIYAGANJ, SIDDHARTH NAGAR (U.P.)

COURSES

UGC, AICTE Approved

B.A., B.com, M.A., M.S.W., NTT, PTT

IGD Bombay Art (By Maharastra Govt.)

CCC, BCC, 'O' Level (By Nielit पूर्व में DOEACC)

RNI No.: UPHIN/2023/87359

तेजस बिन्दु

हिन्दी मासिक पत्रिका मूल्य : ₹50/-

वर्ष:02, अंक-12, जुलाई-2025

संपादक
आरती यादव

सह संपादक
निशा सिंह

प्रबन्ध संपादक
दुर्गावती देवी

विधिक सलाहकार
मानती यादव

संवाददाता
साधना देवी, गीता देवी

मैगजीन लेआउट
ZENTAL PRINT
8881544447

तेजस बिन्दु के लिए स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, आरती यादव द्वारा इशिता प्रिन्टर्स, 168/8, हेवेट रोड़, हुसैनगंज चौराहा, लखनऊ (उ०प्र०)–226001 से मुद्रित एवं 251 ग्रा० लटेरा पो०–धोरहरा डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर (उ०प्र०)–272189 से प्रकाशित।

रजिस्टर्ड कार्यालय
251 ग्रा० लटेरा पो०-धोरहरा डुमरियागंज,
सिद्धार्थनगर (उ०प्र०)-272189
Mob. 9838595489
E-mail:tejasips89@gmail.com

पत्रिका से संबंधित समस्त वाद विवादों का न्याय क्षेत्र सिद्धार्थनगर, उ०प्र० न्यायालय होगा।

सभी पद अवैतनिक है।

इस अंक में

देश की आवाज सामाजिक न्याय के पुरोधा...

...सशक्त संविधान भारत के पास

मनुष्य और प्रकृति के बीच है...

भाजपा-जदयू पर विपक्ष का गंभीर आरोप ...

मा.विधायक सैयदा खातून ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटेरा में ...

सम्पादकीय

पर्यावरण को बचाना बड़ी चुनौती

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से जारी रपट भी इस ओर इशारा करती है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2021 से 2025 के दौरान देश भर में 667 बाघों की मौत हुई है। इनमें से 341 बाघों की मौत अभयारण्यों से बाहर हुई है। देश भर के जंगलों में जिस तरह से अतिक्रमण और खनन के साथ मानवीय हस्तक्षेप बढ़ा है, उससे बाघों का सुरक्षित पर्यावास खतरे में है। वनों की लगातार कटाई ने उनके लिए आहर की चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। जंगलों के भीतर सड़कों के निर्माण और कोलाहल बढ़ने से प्राकृतिक माहौल का संतुलन बिगड़ा है।

नतीजा यह कि अब बाघ जंगलों से बाहर निकल रहे हैं। भोजन-पानी की तलाश में भटकते ये वन्य जीव मनुष्यों के लिए तो खतरा बने ही हैं, साथ ही उनके जीवन पर भी संकट बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की घटनाओं में इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से जारी रपट भी इस ओर इशारा करती है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2021 से 2025 के दौरान देश भर में 667 बाघों की मौत हुई है। इनमें से 341 बाघों की मौत अभयारण्यों से बाहर हुई है। इस रपट ने अभयारण्यों की देखरेख में बरती जा रही लापरवाही को भी उजागर किया है। बाघों के लिए जंगल छोटे पड़ रहे हैं। सवाल है कि अभयारण्यों में आवाजाही के लिए बने गलियारों से बाघ और तेंदुए गांवों एवं शहरों तक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या उनके लिए जंगल छोटे पड़ रहे हैं। क्या बाघों की निगरानी के लिए अब तक मजबूत तंत्र नहीं बन पाया है? अगर कहीं बाड़बंदी नहीं है और बाघ निर्धारित दायरे से बाहर निकलते हैं, तो समय रहते ऐसी घटनाओं का पता क्यों नहीं लगाया जाता। ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक के बावजूद बाघों की नियमित निगरानी क्यों संभव नहीं हो पा रही है।

एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जंगलों में बाघों के लिए भोजन का अभाव है? मध्य प्रदेश में दो दशकों में जिस तरह वनों की कटाई हुई है, उसका परिणाम सामने हैं। यहां चार वर्ष के भीतर अभयारण्यों से बाहर निकले नब्बे बाघों की मौत कोई साधारण घटना नहीं है। शासन व प्रशासन को बाघों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। यह सब आधी-अधूरी योजनाओं से नहीं, बल्कि नवोन्मेषी उपायों से ही संभव हो पाएगा।

सम्पादक

आरती

अमेरिकी टैरिफ

भारत को नुकसान या फायदा..?

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ की घोषणा की है। गौरतलब है कि ट्रंप के 60 देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाया है। इनमें भारत भी शामिल है। अमेरिका ने भारत पर 27 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला किया है। यहां यदि हम टैरिफ की बात करें तो यह वस्तुओं के आयात पर लगाए जाने वाला सीमा शुल्क या आयात शुल्क है, जिसे आयातक की तरफ से सरकार को देना होता है। आम तौर पर कंपनियां इनका बोझ उपयोगकर्ताओं पर डालती हैं। दूसरे शब्दों में, इसका असर आम लोगों की जेब पर ही पड़ता है। वहीं यदि हम जबाबी टैरिफ की बात करें तो यह शुल्क व्यापारिक साझेदारों की तरफ से लगाए जा रहे शुल्क में वृद्धि या उच्च शुल्क के जवाब में लगाया जाता है। अमेरिकी टैरिफ: भारत को नुकसान या फायदा?

ट्रंप की टैरिफ घोषणा से वैश्विक व्यापार पर एक नया असर पड़ना स्वाभाविक ही है। टैरिफ मैन द्वारा टैरिफ की घोषणा के बाद शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई। पाठकों को बताता चलूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला है और मार्केट ओपन होने के साथ ही बीएसई सेंसेक्स व एनएसई निफ्टी बुरी तरह टूट गए।

शेयर बाजार में गिरावट के साथ ही इंडियन करेंसी भी गुरुवार(3 अप्रैल 2025) को टूटी है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे गिरकर 85.78 पर आ गया। न केवल भारतीय बाजार बल्कि यूएस स्टोक मार्केट भी क्रैश हुआ। पाठकों को बताता चलूं कि गुरुवार को एस एंड पी 500 में वर्ष 2020 के बाद से सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट दर्ज की गई। डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 4.0% गिरावट के साथ 40,545.93 पर बंद हुआ। इसने 1,600 अंकों से अधिक का गोता लगाया। ट्रंप के टैरिफ ने निवेशकों में दहशत फैला दी है, और बाजार को लग रहा है कि इससे मंदी, महंगाई और कमजोर मुनाफे का दौर शुरू हो सकता है। कुल मिलाकर अमेरिकी बाजार छह प्रतिशत तक गिरा। मार्केट कैप करीब 2 ट्रिलियन डॉलर घट गया। यहां तक कि एप्पल और नाइकी के शेयर 15 प्रतिशत तक टूट गये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एप्पल के आईफोन मुख्य रूप से चीन में बनाए जाते हैं और ट्रंप के टैरिफ का सबसे बड़ा असर भी चीन पर ही पड़ा है।

बहरहाल, गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर

26 प्रतिशत 'रियायती पारस्परिक शुल्क' लगाने की घोषणा की है जो भारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए 52 प्रतिशत शुल्क का आधा है। पाठकों को बताता चलूं कि ट्रंप ने भारत को 'बहुत कठोर' बताया है। उन्होंने यह बात कही है कि, 'यह मुक्ति दिवस है, एक ऐसा दिन जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 2 अप्रैल 2025 को हमेशा उस दिन के रूप में याद किया जाएगा, जिस दिन अमेरिकी इंडस्ट्री का पुनर्जन्म हुआ, जिस दिन अमेरिका ने नियति को पुनः प्राप्त किया और जिस दिन हमने अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाना शुरू किया।' साथ ही, उन्होंने यह भी कहा है कि 'हम अमेरिका को अच्छा और समृद्ध बनाएंगे।' बहरहाल, जो भी हो डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ घोषणा से वैश्विक व्यापार पर असर पड़ता लाज़िमी ही है। पाठक जानते होंगे कि ट्रंप ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन सभी प्रमुख देशों पर पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की है। उनकी घोषणा के तुरंत बाद ही बाजारों में हलचल देखने को मिली। अमेरिका का दावा है कि भारत पर 26 फीसदी का शुल्क, भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए 52 फीसदी टैरिफ के जवाब में है, जो उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का ही हिस्सा है। दरअसल, ट्रंप यह बात बहुत पहले से ही कहते आए हैं कि यदि कोई देश अमेरिकी सामान पर ज्यादा आयात शुल्क लगाता है, तो अमेरिका भी उस देश से आयात होने वाली चीजों पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा। अमेरिकी टैरिफ: भारत को नुकसान या फायदा..?

कहना ग़लत नहीं होगा कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल है और इसे देखते हुए हाल ही में ट्रंप द्वारा लगाया गया जवाबी शुल्क अप्रत्याशित नहीं है। वास्तव में भारत अमेरिका को काफी वस्तुओं का निर्यात करता है। पाठकों को बताता चलूं कि अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी के तहत भारतीय उत्पादों पर 27 फीसदी तक टैरिफ लगाया जाएगा। इसमें एक यूनिवर्सल 10 फीसदी टैरिफ भी शामिल है, जो 5 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। वहीं, 27 फीसदी टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होगा। अमेरिका द्वारा घोषित इस नए टैरिफ से भारत के कई एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर असर पड़ने की आशंका है। इनमें झींगा मछली, कालीन, गोल्ड जूलरी, चिकित्सा उपकरण जैसे उत्पाद शामिल हैं। गौरतलब है कि अमेरिका भारतीय झींगा मछली का सबसे बड़ा बाजार है और

हाई टैरिफ के कारण भारतीय झींगा अमेरिकी बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगी।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमेरिका पहले से ही भारतीय झींगा पर डंपिंग-रोधी और प्रतिपूरक शुल्क लगा रहा है। भारत अपने झींगा निर्यात का 40% अमेरिका को भेजता है जहां इसके मुख्य प्रतिस्पर्धी इक्वाडोर और इंडोनेशिया हैं। वास्तव में, कृषि क्षेत्र में अमेरिका के जवाबी टैरिफ का सबसे अधिक प्रभाव मछली, मांस और प्रसंस्कृत समुद्री भोजन के निर्यात पर पड़ेगा। वर्ष 2024 में इनका निर्यात 2.58 अरब डॉलर था। अब हालिया घटनाक्रम के बीच इस क्षेत्र पर 27.83 प्रतिशत से अधिक टैरिफ का भार बढ़ सकता है। इसी प्रकार से अमेरिका भारत से बड़ी मात्रा में कालीनों का भी आयात करता है।

जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में यह(कालीन आयात) लगभग 2 अरब डॉलर का था। नए टैरिफ से इस सेक्टर पर भी व्यापक असर पड़ेगा। इतना ही नहीं अमेरिका भारत से रत्न और आभूषणों का भी बड़ी संख्या में आयात करता है।एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने वैश्विक स्तर पर 32.85 अरब डॉलर के रत्न और आभूषण निर्यात किए, जिसमें अमेरिका का हिस्सा 30.28% (10 अरब डॉलर) था। नए टैरिफ से इस सेक्टर पर भी बहुत असर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार तराशे हुए हीरे पर शुल्क 0% से 20% तक और सोने के आभूषणों पर 5.5-7% तक बढ़ सकता है। इतना ही नहीं,अमेरिका द्वारा चिकित्सा उपकरण निर्यात पर 27% टैरिफ लगाने से इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का अमेरिका को चिकित्सा उपकरण निर्यात 71 करोड़ 43.8 लाख डॉलर था।

संक्षेप में कहें तो टैरिफ से हमारे देश के कृषि, ऑटोमोबाइल, दवा, स्वर्ण आभूषण जैसे क्षेत्रों पर बड़ा असर हो सकता है। वहीं, रसायन और दवा क्षेत्र में यह 8.6 प्रतिशत, प्लास्टिक के लिए 5.6, वस्त्र-परिधान 1.4, हीरे, सोने व आभूषणों के लिए 13.3 फीसदी, लोहा, इस्पात और आधार धातुओं के लिए 2.5 प्रतिशत, मशीनरी व कंप्यूटर के लिए 5.3 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7.2 फीसदी व ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए टैरिफ का यह अंतर 23.1 फीसदी है। इतना ही नहीं,प्रसंस्कृत खाद्य, चीनी और कोको निर्यात पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इसमें टैरिफ अंतर 24.99 प्रतिशत है। पिछले साल इसका निर्यात 1.03 अरब डॉलर था। इसी तरह, अनाज, सब्जियां, फल और मसाले के क्षेत्र में टैरिफ अंतर 5.72 प्रतिशत है। वास्तव में,टैरिफ अंतर जितना अधिक होगा, संबंधित क्षेत्र उतना ही अधिक प्रभावित हो सकता है। अमेरिकी टैरिफ: भारत को नुकसान या फायदा..?

घरेलू उद्योग व निर्यातकों ने भारत के निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ के असर को लेकर चिंता जताई है क्योंकि शुल्क से बाजारों में कई वस्तुएं प्रतिस्पर्धा से बाहर हो सकती हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है लेकिन यहां यह कहना ग़लत नहीं होगा कि चीन (34 फीसदी), वियतनाम (46 फीसदी), बांग्लादेश (37 फीसदी), थाईलैंड (36) फीसदी) और इंडोनेशिया

(32 फीसदी) की तुलना में भारत पर लगाया गया टैरिफ कम ही है। इसलिए स्थिति तुलनात्मक रूप से भारत के लिए अच्छी हो सकती है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। अमेरिका की भारत के कुल माल निर्यात में हिस्सेदारी करीब 18%, आयात में 6.22% और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73% है।अमेरिका के साथ 2023-24 में भारत का व्यापार अधिशेष (आयात व निर्यात में अंतर) 35.32 अरब अमेरिकी डॉलर था।

बहरहाल,यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा में फार्मास्युटिकल्स उद्योग को छूट दी गई है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश देश का सबसे बड़ा फार्मा हब है। बद्दी, परवाणू और पांवटा साहिब में देश की सभी प्रतिष्ठित कंपनियां दवाओं का उत्पादन कर रही हैं। पाठकों को बताता चलूं कि ट्रंप ने जब टैरिफ की घोषणा की तो भारत पर 27 फीसदी टैरिफ तो लगाया लेकिन फार्मा उद्योग को इससे पूरी तरह बाहर रखा गया, जो राहत की बात है, लेकिन हिमाचल के बागवानों को शंका है। दरअसल, यह आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अमेरिकी दबाव में भारत सरकार सेब पर आयात शुल्क घटा सकती है। इससे हिमाचल प्रदेश के सेब बागवान चिंतित हो गए हैं। पाठकों को बताता चलूं कि दवा के अलावा सेमीकंडक्टर, तांबे के अलावा तेल, गैस, कोयला, एलएनजी जैसे ऊर्जा उत्पाद टैरिफ के दायरे से बाहर रखे गए हैं। बहरहाल, यदि हम यहां पर भारत पर शुल्क की बात करें तो इस्पात, एल्युमीनियम और वाहनों तथा कलपुर्जों पर पहले से ही 25% शुल्क लागू है। शेष उत्पादों पर 5 से 8 अप्रैल के बीच 10% का मूल (बेसलाइन) शुल्क लगेगा और 9 अप्रैल से बढ़कर 27% हो जाएगा।

भारत के लिए अमेरिका द्वारा लगाया टैरिफ कितनी बड़ी चुनौती है तो इस संबंध में विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की स्थिति अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर है। भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में अपनी भूमिका बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन इसके लिए उसे व्यापार को आसान बनाना होगा, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा। यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगायें हैं वे डब्ल्यूटीओ के अनुरूप नहीं हैं। मसलन,ये शुल्क स्पष्ट तौर पर विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हैं। यह एमएफएन (तरजीही राष्ट्र) दायित्वों तथा बाध्य दर प्रतिबद्धताओं के भी खिलाफ हैं। सदस्य देशों को इनके खिलाफ डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र का दरवाजा खटखटाने का पूरा अधिकार है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने फरवरी में अमेरिका यात्रा के दौरान 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। वास्तव में, दोनों पक्षों का लक्ष्य इस साल अक्तूबर तक सौदे के पहले चरण को अंतिम रूप देना है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत की ओर से अधिकांश चर्चा इन शुल्कों के कुछ प्रतिकूल प्रभावों को कम करने पर केंद्रित होगी। कहना चाहूंगा कि टैरिफ संकट से भारत को अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में विविधता लाने का अवसर प्रदान करेगा।

हालांकि यह भी स्पष्ट है कि ट्रंप की रेसिप्रोक्ल टैरिफ पालिसी असल प्रभाव आने वाले समय में स्पष्ट होगा, लेकिन इसने वैश्विक व्यापार को एक नया मोड़ तो दिया ही है। निस्संदेह यह हमें हमारी आर्थिक नीतियों को फिर से परखने का समय है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज जरूरत इस बात की है कि सरकार व उद्योग मिलकर ऐसी ठोस रणनीतियां बनाएं, जिससे हम टैरिफ आपदा में निहित अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकें। बहरहाल, हमारे देश के लिये अच्छी बात यह है कि हमारे मुख्य प्रतिस्पर्धी-चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और थाईलैंड पर हम से कहीं अधिक शुल्क लगाया गया है। हाल फिलहाल, सरकार को यह उम्मीद है कि वाशिंगटन के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम चल रहा है, जिसके जरिये घरेलू उद्योग को टैरिफ वृद्धि के दुष्प्रभावों से निपटने में मदद मिल सकती है। वास्तव में,अतीत से सबक लेकर भारत को नई स्थितियों का लाभ उठाने के लिये बेहतर ढंग से तैयार रहना चाहिए।

हमें अपने पड़ौसी चीन से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्यों कि चीन भारत को कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा के बाजार में भारत को शिकस्त दे सकता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि चीन कम लागत वाले सामानों के जरिये भारतीय बाजारों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। बहरहाल, कहना चाहूंगा कि आज भारत दुनिया का सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है, इसलिए हमें यह चाहिए कि हम अपनी श्रमशक्ति के बेहतर उपयोग की दिशा में गंभीरता से काम करें। हमें यह चाहिए कि हम कौशल विकास(स्किल डेवलपमेंट) पर अपना ध्यान केंद्रित करें।

कहना ग़लत नहीं होगा कि कुशल कामगारों से हम वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो सकते हैं। इतना ही नहीं, हमें अपना विदेशी निवेश भी बढ़ाना होगा। हमें अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी गति देनी होगी। जरूरत इस बात की है कि हम अपने निर्यात को अन्य देशों में बढ़ाने के लिए काम करें, तभी हम वास्तव में अमेरिकी टैरिफ संकट का सामना करते हुए अपने देश की अर्थव्यवस्था और विकास को और अधिक गति दे पायेंगे। ■

दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और सशक्त संविधान भारत के पास

सर्वप्रथम सन् 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी कि अंग्रेजों के अधीनस्थ भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए लेकिन भारत के लिए स्वतंत्र संविधान सभा के गठन की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया था।

सर्वप्रथम सन् 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी कि अंग्रेजों के अधीनस्थ भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए लेकिन भारत के लिए स्वतंत्र संविधान सभा के गठन की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया था। प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। हालांकि वैसे तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था लेकिन इसे स्वीकृत 26 नवम्बर 1949 को ही कर लिया गया था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण ही भारत का संविधान ऐसे रूप में सामने आया, जिसे दुनिया के कई अन्य देशों ने भी अपनाया। वर्ष 2015 में डॉ. अम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष में पहली बार देश में 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था और इस साल हम 71वां संविधान दिवस मना रहे हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।

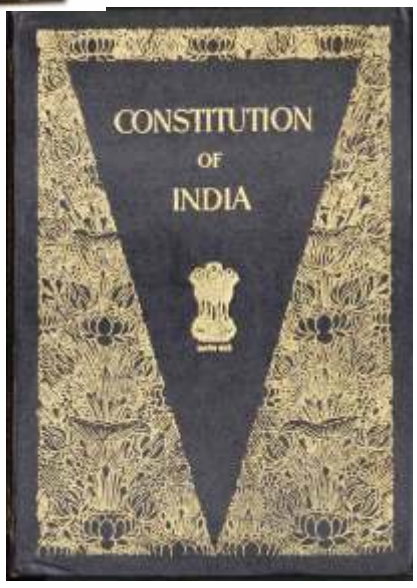

संविधान प्रारूप समिति की बैठकें 114 दिनों तक चली थी और संविधान के निर्माण में करीब तीन वर्ष का समय लगा था। संविधान के निर्माण कार्य पर करीब 64 लाख रुपये खर्च हुए थे और इसके निर्माण कार्य में कुल 7635 सूचनाओं पर चर्चा की गई थी। मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे लेकिन 44वें संविधान संशोधन के जरिये सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 (ए) के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, जिसके बाद भारतीय नागरिकों को छह मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24), धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28), संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30) तथा संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 32) शामिल हैं। संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12

से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन है और संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि इनमें संशोधन भी हो सकता है तथा राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।

भारतीय संविधान से जुड़े रोचक तथ्यों पर नजर डालें तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी रोचक बात यही है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सर्वप्रथम सन् 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी कि अंग्रेजों के अधीनस्थ भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए लेकिन भारत के लिए स्वतंत्र संविधान सभा के गठन की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया था। 1922 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मांग की कि भारत का राजनैतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे लेकिन अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा के गठन की लगातार उठती मांग को ठुकराया जाता रहा। आखिरकार 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ही एकमात्र उपाय है और सन् 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा ही बनाए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया। 1942 में क्रिप्स कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो भारत का संविधान तैयार करेगी।

सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा पहली बार समवेत हुई किन्तु अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को लेकर मुस्लिम लीग द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया। दो दिन बाद संविधान सभा की बैठक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और वे संविधान बनाने का कार्य पूरा होने तक इस पद पर आसीन रहे। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ और संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने वाली 'संविधान निर्मात्री समिति' का गठन किया गया, सर्वसम्मति से जिसके अध्यक्ष बने भारतीय संविधान के जनक डॉ. भीमराव अम्बेडकर। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए संविधान में पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की गई है, जिससे भारतीय संविधान का सार, उसकी अपेक्षाएं, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना के अनुसार, ''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।'' संविधान की यह प्रस्तावना ही पूरे संविधान के मुख्य उद्देश्य को प्रदर्शित करती है। ■

डिजिटल अरेस्ट

देश भर में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिसमें साइबर ठगी करने वाले कई तरीके अपना रहे हैं जैसे, फिशिंग, हैकिंग, विशिंग , एटीम स्वैपिंग ,डिजिटल अरेस्ट आदि ।जिसमें इन दिनों साइबर ठग धोखाधड़ी के लिए सबसे अधिक डिजिटल अरेस्ट स्कैम कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के जरिये करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओ में हम सब को सतर्क रहने की जरूरत हैं । क्या आप जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट की पहचान कैसे करें और इससे बचने के लिए क्या करें? चलिए हम सब डिजिटल अरेस्ट को विस्तार से समझते है.....क्या है डिजिटल अरेस्ट?डिजिटल अरेस्ट एक साइबर ठगी क्विक तरीका है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फोन करने वाले कभी पुलिस,कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स,कभी आरबीआई और तो और कभी कभी दिल्ली या मुंबई पुलिस कस्टम अधिकारी बनकर आत्मविश्वास से बात करते हैं। वॉट्सएप या स्काइप कॉल पर जब कनेक्ट करते हैं तो आपको फर्जी अधिकारी एकदम असली से लगते हैं। वे लोग पीड़ित इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करते हैं।जैसे कभी बोलेंगे कि आप का लड़का गलत काम करते हुए पकड़ा गया है ,अभी थाने में है उसके नाम से एफ आई आर न दर्ज हो उसके लिए पैसे की डिमांड करेंगे,कभी बोलेंगे कि आप के पुत्र या पिता जी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट करने या ऑपरेशन के लिए तुरंत पैसे भेजे नहीं तो उसकी जान जा सकती है कहने का मतलब ये है कि वो आप को इमोशनली और मेंटली आप के साथ खेलेंगे। ऐसे में ज्यादातर लोग डर जाते हैं और उनके जाल में फंसते चले जाते हैं।आसान भाषा में कहा जाए तो डिजिटल अरेस्ट में फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर ऑडियो,वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को डरा-धमकाकर उनसे बड़ी रकम वसूली जाती है।डिजिटल अरेस्ट को पहचाने कैसे....अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आती है।किसी में फंसने या परिजन के किसी मामले में पकड़े जाने का जानकारी दी जाती है।धमकी देकर वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए मजबूर किया जाता है।स्कैमर्स मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स का धंधा या अन्य अवैध गतिविधियों का आरोप लगाते हैं।पीड़ित को परिवार या फिर किसी को भी इस बारे में कुछ न बताने की धमकी दी जाती है।वीडियो कॉल करने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा

नजर आता है।पीड़ित को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है या मदद कर रही है।केस को बंद करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए मोटी रकम की मांग की जाती है।इस प्रकार के हरकत मिलने पर तुरंत सतर्क हो जाएं, घबराएं नहीं और न ही जल्दबाजी दिखाए,क्योंकि कोई भी सरकारी जांच एजेंसी आधिकारिक संचार के लिए वॉट्सएप या स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग नहीं करतीं,न ही पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बात करने से रोकती है।डिजिटल अरेस्ट की रिपोर्टअगर आप ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, तो तुरंत अपने कार्ड को ब्लॉक करने के लिए ग्राहक सेवा पर कॉल करें आपका पहला चरण अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने के लिए तुरंत अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करना है. धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन को हाइलाइट करें और ग्राहक सेवा को सूचित करें ताकि कोई और नुकसान न हो. आप यह सुनिश्चित करे कि आप औपचारिक शिकायत के साथ आगे बढ़ने से पहले अपने अकाउंट को सुरक्षित करें. धोखाधड़ी से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करें औपचारिक शिकायत दर्ज करने से पहले, सभी आवश्यक प्रमाण एकत्र करें पिछले छह महीनों की बैंक स्टेटमेंट, आपके द्वारा क्लिक किए गए किसी भी धोखाधड़ी भरे एसएमएस मैसेज या संदिग्ध लिंक, ऐप या वेबसाइट के स्क्रीनशॉट,आपकी निजी जानकारी जैसे आईडी और पते का प्रमाण,इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखने से शिकायत प्रक्रिया में आप को काफी आसानी होगा।साइबर क्राइम सेल (ऑनलाइन या ऑफलाइन) के साथ शिकायत दर्ज करें आप साइबर क्राइम सेल के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं. साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर को 1930 में अपडेट किया गया है, जो कार्य दिवसों पर सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध है. या, cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकतें हैं ।अगर आप किसी भी साइबर क्राइम सेल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप Fir (फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) फाइल करने के लिए अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर भी जा सकते हैं. आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 154 के अनुसार, प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अपनी शिकायत को रजिस्टर और रिकॉर्ड करना होगा, भले ही उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो ।सतर्क रहें, सुरक्षित रहे।

मनुष्य और प्रकृति के बीच है एक शाश्वत रिश्ता

हाल ही में जम्मू-कश्मीर में बादल फट जाने से बहुत तबाही मची।सच तो यह है कि प्रकृति समय-समय पर मानव को अपना प्रकोप दिखा रही है और कहीं न कहीं मानव को आगाह कर रही है कि अभी भी यदि हमने अपने पर्यावरण और प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमें और भी अधिक प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हाल ही में रामबन जिले के सेरी बागना इलाके में 20 अप्रैल को सुबह बारिश के बाद बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया। बादल फटने की इस दुखद घटना(तीन लोगों की मौत पर) पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं।नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से प्रभावित परिवारों को पर्याप्त राहत प्रदान करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता का अनुरोध करने की बात कही है। बहरहाल, जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर में की दिनों से बारिश हो रही है और बादल फटने से अचानक बाढ़ आने के कारण पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आ गया, जिसकी चपेट में कई लोग और घर आ गए। किश्तवाड़ में तो पूरा पहाड़ दरक गया बताया जा रहा है। मनुष्य और प्रकृति के बीच है एक शाश्वत रिश्ता

जानकारी के अनुसार रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड(भूस्खलन) हुई हैं। इसके कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बारिश व लैंडस्लाइड के कारण सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं और किश्तवाड़-पद्दर मार्ग भी बंद बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है और अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की अपील की है। पाठक जानते होंगे कि भूकंप, बाढ़, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, सूखा, हिमस्खलन, ओलावृष्टि, और तूफ़ान जैसी घटनाएं प्राकृतिक प्रकोप या आपदाओं के अंतर्गत आतीं हैं। इससे हमारे पर्यावरण, हमारी पारिस्थितिकी, मानव को तो नुकसान होता ही है, ऐसी घटनाओं से आर्थिक नुकसान भी पहुंचता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण दबाव बढ़ता है। हालांकि, प्रकृति का मनुष्य के पास आज भी कोई तोड़ नहीं है और हम प्रकृति का कभी सामना नहीं कर सकते हैं। प्रकृति के प्रकोपों के लिए कहीं न कहीं हम मानव ही कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। वास्तव में हमें यह चाहिए कि हम किसी भी हाल और परिस्थितियों में प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करें ,क्योंकि प्रकृति मनुष्य के साथ ही धरती के सभी जीव-जंतुओं के लिए बहुत अहम और महत्वपूर्ण है।

पाठक जानते हैं कि प्रकृति से हमें भोजन, पानी, दवा, ईंधन, आश्रय, और ऑक्सीजन प्राप्त होती है।सच तो यह है किप्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 'दश कूप समा वापी, दशवापी समोह्रदः। दशह्रद समः पुत्रों, दशपुत्रो समो द्रमुः।।' इसका भावार्थ यह है कि एक पेड़ दस कुओं के बराबर,एक तालाब दस सीढ़ी के कुएं के बराबर, एक बेटा दस तालाब के बराबर, एक पेड़ दस बेटों के बराबर होता है। बहरहाल,यह प्रकृति ही के कारण है कि इस धरती पर हमारा, जीव-जंतुओं और वनस्पतियों का अस्तित्व संभव है। आज मनुष्य अपने स्वार्थों और लालच के चलते प्राकृतिक संसाधनों का असीमित और अंधाधुंध दोहन कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राकृतिक संसाधनों का संयमी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। प्रकृति में संसाधनों की कमी नहीं है, यदि हम इनका विवेकपूर्ण तरीके से और संयमी

इस्तेमाल करें। आज हम कहने को तो प्रकृति के प्रति जागरूक हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम लगातार खनन, पेड़ों की कटाई, पानी व खनिज संसाधनों का दोहन करने में लगे हैं।

विकास के नाम पर हमने प्रकृति को आज कहीं का नहीं छोड़ा है। आज अंधाधुंध प्रदूषण (मिट्टी, वायु,जल) फैलाया जाता है, लेकिन इसको ढंग से प्रबंधित नहीं किया जाता है। जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है, जैसा कि आबादी बढ़ने के साथ ही इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, हालांकि आज जीवाश्म ईंधन को कम करने के लिए इलैक्ट्रिक वाहनों और अन्य ईंधनों पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन हमें प्रकृति संरक्षण के लिए और अधिक आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है।सच तो यह है कि आज मानव को जरूरत इस बात की है कि वह प्रकृति से नाता जोड़ें और लालच और स्वार्थ से नाता तोड़े। वास्तव में हम मनुष्यों ने आज पर्यावरण और प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कहना ग़लत नहीं होगा कि अंधाधुंध विकास ने हमारे पूरे प्राकृतिक चक्र को बिगाड़ कर रख दिया है।हम जल, जंगल और जमीन का संरक्षण कृतसंकल्पित होकर नहीं कर पा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में शुरू से ही प्रकृति और पर्यावरण को विशेष महत्त्व दिया गया है और यहां तक कहा गया है कि 'माता भूमि: पुत्रो अहं पृथिव्या:' अर्थात यह पृथ्वी ही हमारी माता है और हम सभी देशवासी इस धरा की संतान हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों, जल, वायु, अग्नि, नदियों, समुद्र, और धरती को पूज्य माना गया है।

आज कुंआ, सरोकार, तालाब, झीलें, जोहड़ पहले की तुलना में कम रह गये हैं,उनका पुनरूद्धार नहीं हो पा रहा है। वास्तव में, आज पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए सामूहिक और व्यापक-आधारित कार्रवाई की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक सीमाओं के पार लोगों को शामिल करने वाले संरक्षण प्रयासों की ज़रूरत है। आज जरूरत इस बात की है कि हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनें। हमें वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन करना होगा। बहरहाल, यहां यह कहना ग़लत नहीं होगा कि आज हमने अंधाधुंध विकास को ही सब कुछ मान लिया है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। आज धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, प्रदूषण के बारे में तो कहना ही क्या ? हमने नदियों के जल को पानी या विद्युत स्रोत मान कर उनका दोहन किया। नदियों को प्रदूषण का केंद्र बना डाला है। मिट्टी, वायु प्रदूषित हो चुके हैं। हम फसलों के अवशेषों को जलाते हैं। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग कम करते हैं। अंधाधुंध निर्माण कार्य कर रहे हैं। वास्तव में पहले के जमाने में हमारा प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहन सम्मान था और हम पारिस्थितिकीय परस्पर निर्भरता के प्रति जागरूक थे, शायद आज उतने जागरूक और संवेदनशील हम नहीं रहे, क्यों कि इसमें हमारा स्वार्थ और लालच आड़े आ गया है।हम प्रकृति से सबकुछ छीन कर अपनी गोदी में भर लेना चाहते हैं।

वास्तव में आज जरूरत इस बात की है कि आज हम मानव समाजों के साथ-साथ पर्यावरण के अस्तित्व और कल्याण की गारंटी पर कृतसंकल्पित होकर ईमानदारी से काम करें। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि जम्मू-कश्मीर में जो तबाही आई है, उसके लिए कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही, मिलीभगत या भ्रष्टाचार को जिम्मेदार माना जा सकता है। वास्तव में, आज हमारा समाज इतना लालची व स्वार्थी हो गया है कि इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों की भी कोई परवाह नहीं रह गई है। आज हम प्रकृति को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। क्या यह हमारे की विडंबना नहीं है कि आज हमारे देश में गोचर भूमि ,वन भूमि पर अत्यधिक अतिक्रमण हो रहे है। वहां कंक्रीट की दीवारें (आवासीय भवन) खड़े किए जा रहे है। आज पशु-पक्षियों, पेड़ों , वनस्पतियों की अनेक जातियाँ लुप्त होती जा रही हैं। हमारे जल स्रोत आज कचरादान बनते जा रहे है। रिसाइकिल(पुनर्चक्रण) की ठोस व्यवस्थाएं नहीं हैं। प्लास्टिक प्रदूषण ने इस धरती का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जिन नदियों को हम मातृवत् पूजते रहे हैं, अब उनमें कल-कारखानों का प्रदूषित जल(रासायनिक व गंदा जल)प्रवाहित हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज हमारी पुरातन परम्पराएं और रीति-रिवाज समाप्त प्रायः हो गये है।

वर्तमान सभ्यता(पाश्चात्य संस्कृति)और भौतिकता की विषबेल इतनी फलित हो गई हैं कि इसने हमारे देश की समग्र संस्कृति को खत्म प्रायः सा कर दिया है। पाश्चात्य संस्कृति हम सब पर हावी होती चली जा रही है। वास्तव में आज हम सब यह भूल चुके हैं कि 'पर्यावरणनाशेन, नश्यन्ति सर्वजन्तवः।पवनः दुष्टतां याति, प्रकृतिर्विकृतायते।' अर्थात पर्यावरण के प्रदूषित होने से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 'शाश्वतम्, प्रकृति-मानव-सङ्गतम्,सङ्गतं खलु शाश्वतम्।तत्त्व-सर्व धारकं सत्त्व-पालन-कारकं वारि-वायु-व्योम-वह्नि-ज्या-गतम्। शाश्वतम्, प्रकृति-मानव-सङ्गतम्।।' इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच का संबंध शाश्वत है।यह रिश्ता शाश्वत है।जल, वायु, आकाश के सभी तत्व,अग्नि और पृथ्वी वास्तव में धारक हैं और जीवों के पालनहार। बहरहाल, पर्वतीय राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाद अब जब जम्मू-कश्मीर में तबाही आई है, तो इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है , बल्कि आज हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि आखिर हम कब तक प्रवृति से खिलवाड़ करके अपने जीवन को संकट में डालते रहेंगे। अंत में यही कहूंगा कि मानव और प्रकृति का रिश्ता एक अटूट रिश्ता है। मसलन, सूर्य धरती के समस्त जीवों और वनस्पतियों के जीवन का स्रोत है, यह धरती हम सभी का घर है,वायु प्राणशक्ति की संचालक है, और जल जीवन का असली आधार है।प्रकृति हमें निःस्वार्थ भाव से सब कुछ देती है, वैसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहें और उसकी रक्षा करें। ■

जाति के नाम पर सनातन परंपरा हुई शर्मसार

इटावा में जाति के नाम पर धर्म का अपमान, सनातन परंपरा हुई शर्मसार। जब धर्म और जाति के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, तब अक्सर धर्म की आड़ में अधर्म फलने लगता है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से हाल ही में सामने आई घटना न केवल एक निर्दोष भक्त का अपमान है, बल्कि सनातन धर्म की आत्मा—समभाव और सहिष्णुता—पर सीधा प्रहार है। भारत जैसे महान देश का सबसे बड़ा प्रदेश—उत्तर प्रदेश—जहाँ प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान श्रीकृष्ण की लीलास्थली मथुरा है, माँ विंध्यवासिनी का पावन धाम है, जहाँ त्रिवेणी संगम पवित्रता की प्रतीक है, और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी आत्मा को मोक्ष का द्वार दिखाती है—वहीं की धरती से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे सनातन समाज को शर्मसार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दादरपुर में घटित एक घटना ने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हलकों में उबाल ला दिया है। भागवत कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ कथित रूप से की गई अभद्रता, मारपीट और जातिगत अपमान ने न केवल सनातन परंपरा की आत्मा को झकझोरा है, बल्कि समाज की उस मानसिकता को भी उजागर कर दिया है, जो आज भी जातीय श्रेष्ठता के भ्रम में जी रही है। यह घटना न केवल धार्मिक भावना को आहत करती है, बल्कि सामाजिक समानता, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों और सनातन परंपरा की आत्मा—समभाव—का खुला उल्लंघन भी है। यह प्रश्न अब केवल एक गांव का नहीं, बल्कि उस पूरे विचार का है जो धर्म को जाति की जंजीरों से मुक्त देखना चाहता है। मुकुट मणि यादव का आरोप है कि वह गांव में श्रीमद्भागवत कथा कहने पहुंचे थे, जहां आयोजकों में से कुछ लोगों ने उनकी जाति पूछी। जब यह सामने आया कि वे यादव समुदाय से हैं, तो उनके साथ न केवल कथा रुकवा दी गई, बल्कि उन्हें मंच से हटाकर

गाली-गलौज की गई, उनकी चोटी काटी गई, सिर मुंडवा दिया गया और कथित तौर पर उन्हें महिला के सामने नाक रगड़वाकर माफी मांगने के लिए विवश किया गया। आरोपों के अनुसार, उनके चेहरे पर पेशाब तक डाला गया और हारमोनियम तोड़ दिया गया। यह घटना कैमरे में कैद हुई और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, प्रदेशभर में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं।

भागवत कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ कथित रूप से की गई अभद्रता, मारपीट और जातिगत अपमान ने न केवल सनातन परंपरा की आत्मा को झकझोरा है, बल्कि समाज की उस मानसिकता को भी उजागर कर दिया है, जो आज भी जातीय श्रेष्ठता के भ्रम में जी रही है। मुकुट मणि यादव का आरोप है कि वह गांव में श्रीमद्भागवत कथा कहने पहुंचे थे, जहां आयोजकों में से कुछ लोगों ने उनकी जाति पूछी। जब यह सामने आया कि वे यादव समुदाय से हैं, तो उनके साथ न केवल कथा रुकवा दी गई, बल्कि उन्हें मंच से हटाकर गाली-गलौज की गई, उनकी

चोटी काटी गई, सिर मुंडवा दिया गया और कथित तौर पर उन्हें महिला के सामने नाक रगड़वाकर माफी मांगने के लिए विवश किया गया। आरोपों के अनुसार, उनके चेहरे पर पेशाब तक डाला गया और हारमोनियम तोड़ दिया गया। यह घटना कैमरे में कैद हुई और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, प्रदेशभर में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं।

जाति के नाम पर धर्म का चीरहरण

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को जातिगत वर्चस्व की पराकाष्ठा बताते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लखनऊ में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अब कथा कहने के लिए जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य हो गया है, तो योगी सरकार को इस पर कानून बना देना चाहिए। उन्होंने मुकुट मणि यादव और संत सिंह यादव को सम्मानित करते हुए 21-21 हजार रुपये की राशि भेंट की और पार्टी की ओर से 51-51 हजार रुपये देने की घोषणा की। उनका कहना था कि यह घटना भाजपा शासित प्रदेशों में PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के प्रति निरंतर अपमानजनक व्यवहार का उदाहरण है। लेकिन जैसे-जैसे राजनीतिक हलचल तेज हुई, यह मामला कई और मोड़ों पर जा पहुंचा। कथावाचकों के पक्ष में यादव महासभा, समाजवादी पार्टी और अन्य संगठन खड़े हो गए। वहीं दूसरी ओर, गांव की ही महिला रेनू तिवारी और उनके पति जयप्रकाश तिवारी सामने आए और कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाए। रेनू तिवारी का कहना है कि कथा के दौरान भोजन के समय कथावाचक ने उनकी अंगुली पकड़ने की कोशिश की, जिससे उन्हें असहजता हुई। उन्होंने तुरंत अपने पति को जानकारी दी और गांव के कुछ युवा आक्रोशित हो उठे। महिला पक्ष का दावा है कि कथावाचक ब्राह्मण बनकर गांव में पहुंचे थे और जब सच्चाई सामने आई, तो विवाद गहराया। आरोप लगाया गया कि कथावाचक ने फर्जी आधार कार्ड से अपनी जाति ब्राह्मण दर्शाई थी।

अब मामला एक नया मोड़ लेता दिख रहा है, जहां पीड़िता महिला की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की बात सुनकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। पुलिस ने अब तक चार लोगों आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, मनु दुबे और निक्की अवस्थी को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कथावाचकों से मारपीट की थी। हालांकि अब कथावाचकों के आधार कार्ड को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसमें एक ही फोटो पर अलग-अलग नाम और जाति दर्ज हैं। यह तथ्य पुलिस की जांच को और जटिल बना रहा है।इस घटनाक्रम के बाद ब्राह्मण महासभा ने भी मोर्चा खोल दिया है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे ने कहा कि कथावाचक समाज को गुमराह कर ब्राह्मण बनकर कथा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी महिला के साथ यदि छेड़खानी हुई है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि केवल एक पक्ष के आधार पर कार्रवाई की गई तो महासभा आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगी। उनका तर्क है कि कोई भी कथा कह सकता है, लेकिन कथा की आड़ में दुर्व्यवहार की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इधर, समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम एक साजिश है, ताकि कथावाचकों को झूठे आरोपों में फंसाकर जातीय गोलबंदी को तोड़ा जा सके। सपा इटावा जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य का कहना है कि महिला की शिकायत विवाद के दो दिन बाद सामने आई, जब राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या यादव हिंदू नहीं हैं..? क्या उन्हें कथावाचक बनने का अधिकार नहीं..? उन्होंने कहा कि यह सब कुछ PDA समाज को अपमानित करने की साजिश का हिस्सा है। यह पूरा विवाद अब धर्म और जाति के उस चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है, जहां सनातन परंपरा के मूल विचारों की परख हो रही है। क्या कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है..? अगर हम शास्त्रों और धर्मग्रंथों की ओर देखें तो स्पष्ट होता है कि ऐसा कोई विधान नहीं है। स्वयं महर्षि वेदव्यास, जिनके नाम पर व्यास पीठ की परंपरा है, वर्णसंकर थे। उनके पिता महर्षि पाराशर और माता मत्स्यगंधा (सत्यवती) थीं, जो निषाद कन्या थीं। सूत जी, जो भागवत पुराण के मुख्य वाचक माने जाते हैं, वे भी वर्णसंकर थे। शबरी एक वनवासी भीलनी थीं, लेकिन श्रीराम ने उनके प्रेम को पूजा का सर्वोच्च रूप माना। व्याध गीता में एक शिकारी, एक ब्राह्मण सन्यासी को कर्मयोग का उपदेश देता है। प्रह्लाद दैत्यकुल में जन्मे थे, लेकिन उन्हें भक्तराज की उपाधि मिली। यह सभी उदाहरण इस बात का प्रमाण हैं कि सनातन धर्म में ज्ञान, भक्ति और साधना ही सर्वोपरि मानी गई है,जाति नहीं। ■

देश की आवाज

सामाजिक न्याय के पुरोधा

लालू प्रसाद यादव

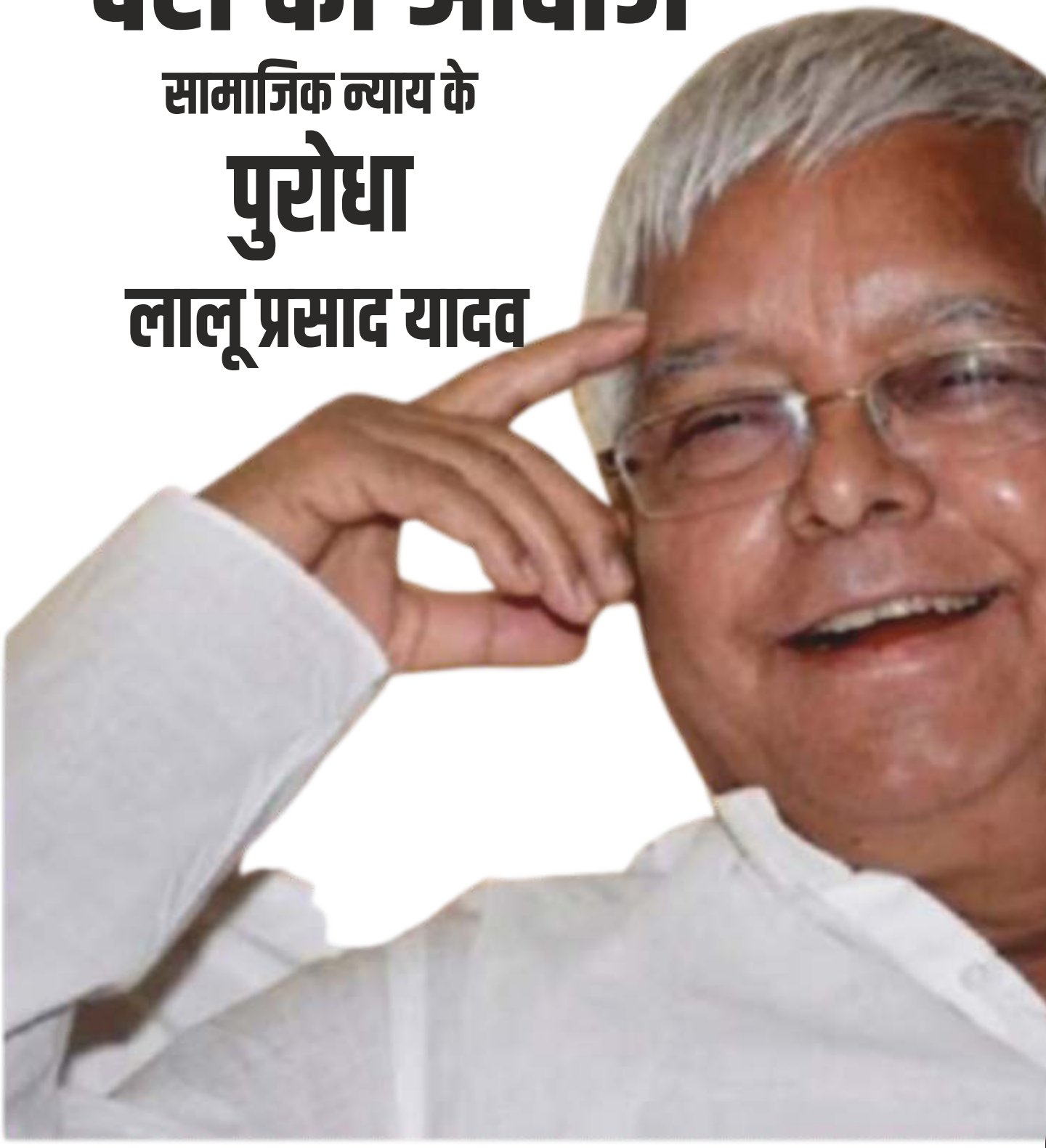

आरपी यादव ब्यूरो, बिहार

देश के राजनैतिक इतिहास में यदि किसी एक नेता ने सामाजिक न्याय की लौ जलाकर शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित वर्गों को आवाज दी, तो वह नाम है – लालू प्रसाद यादव। गोपालगंज की ऐतिहासिक धरती पर जन्मे लालू यादव ने न केवल बिहार की सियासत की तस्वीर बदली, बल्कि एक ऐसी सामाजिक क्रांति की नींव रखी, जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा।गरीबों की जुबान, शोषितों का अधिकार : वह समय जब समाज में गरीबों को खटिया पर बैठने का हक नहीं था, खेतों में घास काटने से रोका जाता था, सामंतवादी मानसिकता हावी थी उस अन्याय के विरुद्ध लालू प्रसाद यादव ने आवाज उठाई। उन्होंने व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। 1990 के दशक में उन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय और समानता की एक नई लकीर खींची। राजनीतिक प्रतीक और संघर्ष की मिसाल : समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हो या विधानसभा में उनके तेजस्वी भाषण, लालू यादव ने हर मोर्चे पर स्पष्ट किया कि बिहार में दंगे, भेदभाव या अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरीबों को सत्ता के केंद्र में लाकर, उन्होंने बताया कि लोकतंत्र केवल सत्ता की नहीं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी हिस्सेदारी है। वर्तमान सियासत पर सवाल:जहां एक ओर लालू राज को आज 'जंगलराज' कहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लाखों गरीब, किसान, मजदूर वर्ग आज भी उस दौर को "स्वर्णिम युग" मानते हैं। वर्तमान सरकारों द्वारा उन्हें बार-बार सियासी साजिशों के तहत घसीटा जा रहा है। जेल की सलाखों के पीछे डाले जाने के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध की बू साफ झलकती है। मनुवादी बनाम जनवादी सोच : लालू यादव की राजनीति हमेशा मनुवादी और सामंतवादी सोच के खिलाफ जनवादी चेतना की राजनीति रही है। यही कारण है कि उनके संघर्षों को दबाने की हर कोशिश के बावजूद वे आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनका जीवन, भाषण, कार्यशैली और साहस – सबकुछ आज भी प्रेरणा का स्रोत है। देश की धरती पर लालू प्रसाद यादव एक ऐसे अनमोल रत्न हैं, जिनकी विचारधारा और काम समाज के सबसे कमजोर वर्गों को ताकत देने का काम करते हैं। इतिहास उन्हें केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में याद रखेगा।"लालू यादव कोई नाम नहीं, एक विचार है – जो तब तक जिंदा रहेगा जब तक गरीब की रोटी, सम्मान और अधिकार की बात जीवित रहेगी।"■

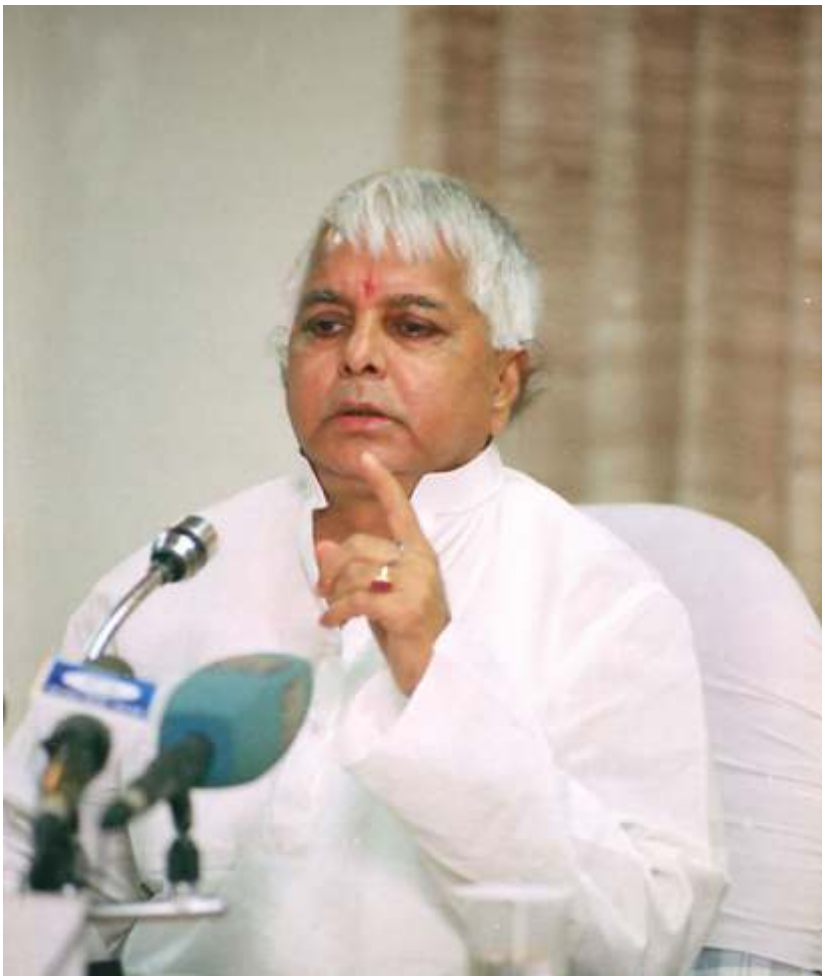

भाजपा-जदयू पर विपक्ष का गंभीर आरोप "मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग की साजिश!

आरपी यादव ब्यूरो, बिहार

देश के राजनैतिक इतिहास में यदि किसी एक नेता ने सामाजिक न्याय की लौ जलाकर शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित वर्गों को आवाज दी, तो वह नाम है – लालू प्रसाद यादव। गोपालगंज की ऐतिहासिक धरती पर जन्मे लालू यादव ने न केवल बिहार की सियासत की तस्वीर बदली, बल्कि एक ऐसी सामाजिक क्रांति की नींव रखी, जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा।गरीबों की जुबान, शोषितों का अधिकार : वह समय जब समाज में गरीबों को खटिया पर बैठने का हक नहीं था, खेतों में घास काटने से रोका जाता था, सामंतवादी मानसिकता हावी थी उस अन्याय के विरुद्ध लालू प्रसाद यादव ने आवाज उठाई। उन्होंने व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। 1990 के दशक में उन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय और समानता की एक नई लकीर खींची। राजनीतिक प्रतीक और संघर्ष की मिसाल : समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हो या विधानसभा में उनके तेजस्वी भाषण, लालू यादव ने हर मोर्चे पर स्पष्ट किया कि बिहार में दंगे, भेदभाव या अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरीबों को सत्ता के केंद्र में

लाकर, उन्होंने बताया कि लोकतंत्र केवल सत्ता की नहीं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी हिस्सेदारी है। वर्तमान सियासत पर सवाल:जहां एक ओर लालू राज को आज 'जंगलराज' कहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लाखों गरीब, किसान, मजदूर वर्ग आज भी उस दौर को "स्वर्णिम युग" मानते हैं। वर्तमान सरकारों द्वारा उन्हें बार-बार सियासी साजिशों के तहत घसीटा जा रहा है। जेल की सलाखों के पीछे डाले जाने के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध की बू साफ झलकती है। मनुवादी बनाम जनवादी सोच : लालू यादव की राजनीति हमेशा मनुवादी और सामंतवादी सोच के खिलाफ जनवादी चेतना की राजनीति रही है। यही कारण है कि उनके संघर्षों को दबाने की हर कोशिश के बावजूद वे आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनका जीवन, भाषण, कार्यशैली और साहस – सबकुछ आज भी प्रेरणा का स्रोत है। देश की धरती पर लालू प्रसाद यादव एक ऐसे अनमोल रत्न हैं, जिनकी विचारधारा और काम समाज के सबसे कमजोर वर्गों को ताकत देने का काम करते हैं। इतिहास उन्हें केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में याद रखेगा।"लालू यादव कोई नाम नहीं, एक विचार है – जो तब तक जिंदा रहेगा जब तक गरीब की रोटी, सम्मान और अधिकार की बात जीवित रहेगी।"■

यदुवंशी एकता संगठन का समाज सुधार की दिशा में बड़ा कदम

आरपी यादव ब्यूरो, बिहार

यदुवंशी एकता संगठन, जो कि बेगूसराय सहित पूरे बिहार में समाज सेवा के लिए समर्पित एक प्रतिष्ठित संगठन के रूप में जाना जाता है, ने एक अहम और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। संगठन ने घोषणा की है कि अब समाज में व्याप्त दहेज प्रथा और मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।संगठन प्रमुख ने बताया कि परंपरागत भोज की व्यवस्थाएं, जो समाज पर आर्थिक बोझ डालती थीं, अब समाप्त की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहले जहां "84 चटिया भोज" जैसी भारी भरकम परंपराएं समाज में प्रचलित थीं, अब संगठन ने इसका विकल्प तैयार कर लिया है। अब भोज की व्यवस्था पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर सामूहिक एवं सादगीपूर्ण रूप से करने का आह्वान किया जाएगा।यदुवंशी एकता संगठन गांव-गांव जाकर समाज को इस मुद्दे पर जागरूक करेगा और लोगों को समझाएगा कि इन कुरीतियों से छुटकारा पाकर ही समाज सशक्त और समानता आधारित बन सकता है। संगठन का उद्देश्य सिर्फ परंपरा तोड़ना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए जिनमें जिला अध्यक्ष अर्जुन यादव, सूरज यादव, आर.पी. यादव, जया किशोर यादव, मनोज यादव, बाल्मीकि यादव, अभिमन्यु यादव, संतोष यादव, लक्ष्मी नारायण यादव, कौशल यादव, सुबोध यादव और ललित यादव प्रमुख रूप से उपस्थित थे। साथ ही सैकड़ों यदुवंशी समाज के लोग इस ऐतिहासिक निर्णय के साक्षी बने।संगठन ने समाज से भी इस प्रयास में साथ देने की अपील की है ताकि एक स्वस्थ, समरस और कुरीतियों से मुक्त यदुवंशी समाज की स्थापना हो सके। ■

बेखौफ अपराध, गूंगी सियासत

बिहार की वर्तमान सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति को लेकर वरिष्ठ पत्रकार आरपी यादव (निवासी, बेगूसराय) ने गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राज्य एक बेहद कठिन और संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। सरकारें वादे तो बहुत कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आम जनता खुद को असहाय महसूस कर रही है। आरपी यादव ने कहा कि बेगूसराय में हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। इन घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि समाज का हर वर्ग - बुजुर्ग, किसान, नौजवान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित और वंचित-इस स्थिति में मौन होकर रह गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस हालात के बीच बिहार किस दिशा में जाएगा? और अफसरशाही व राजनीतिक तंत्र के बीच पिसती जनता को कौन राहत देगा? आरपी यादव का कहना है कि अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल - चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) हो या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल यूनाइटेड (जदयू)

हो या कांग्रेस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो या लोजपा (चिराग गुट या पारस गुट)- सभी को एक साथ मिलकर बेगूसराय और बिहार के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की चुप्पी खतरनाक है और यदि राजनीतिक दल अब भी नहीं चेते तो बिहार की स्थिति और बिगड़ सकती है। यह खबर समाज के हर वर्ग को जागरूक करने और जिम्मेदारियों की याद दिलाने का प्रयास है। ■

माननीया विधायक सैयदा खातून ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटेरा में किया वृक्षारोपण

संवाददाता - राम चंद्र

डुमरियागंज की विधायक माननीया श्रीमती सैयदा खातून ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटेरा में वृक्षारोपण कर पेड़ों के महत्व को समझाया।

उन्होंने कहा कि वृक्ष धरा के आभूषण हैं, इनके बिना जीवन संभव नहीं है।

वातावरण में प्रदूषण पर नियंत्रण रखने और मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए ए पेड़ पौधे किसी वरदान से कम नहीं हैं। हम सभी को पर्यावरण को बचाने की यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जहां भी पेड़ लगाने योग्य भूमि मिले हमें आने वाले पीढ़ी के लिए वृक्ष जरूर लगाना चाहिए ताकि हम उन्हें स्वच्छ वायु दे सकें। वृक्षारोपण कार्यक्रम के इस अवसर चिकित्सा अधीक्षक डॉ रजनीश पाठक, विश्व पिछड़ा परिषद के संस्थापक डॉ तेजस यादव, सपा नेता बहरैची प्रसाद प्रेमी,

फार्मासिस्ट विनोद कुमार, एक्स रे टेक्नीशियन जय सिंह, स्टाफ नर्स जागृति पटेल स्वास्थ्य कर्मी शिवकुमारी, गीता यादव तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राजनीति में धर्म और जातीय समीकरण से बिगड़ा समाज का ताना-बाना।

भारतीय राजनीति में जब से धर्म और जाति देखकर चुनाव में टिकट दिया जाने लगा तथा जातियों - जातियों का संगठन बनने लगा तो अब और घृणा समाज में फैलने लगी, यह इतना फैल गया कि अब देश हित और समाज हित के मुद्दे पीछे छूटते चले गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीकी,जैसा विषय अब महत्वहीन हो गया, भारत के राजनैतिक इतिहास में इतना नैतिक पतन कभी नहीं हुआ।अब तो हर तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ दिख रहा है और परमार्थ विलुप्त होता जा रहा है।

राम चन्द्र

अगर सामाजिक एकरूपता स्थापित करना है तो देश के युवाओं को आगे आना होगा तथा जाति पाति की राजनीति से ऊपर उठकर समान मनोभाव से देशहित की जिम्मेदारी लेकर समाज को आगे ले जाना होगा,वरना दुनिया फिर हम पर हसेगी कि आजादी के 75 साल बाद भी भारत में ग़रीबी, अशिक्षा, भुखमरी, परनिर्भरता बनी हुई है। आओ पहल करें स्वार्थ छोड़ परमार्थ की तरफ़ आगे बढ़े।

एनीमिया अर्थात रक्ताल्पता का रोग

खून में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने को एनीमिया अर्थात रक्ताल्पता का रोग कहा जाता है। आयरन हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये कोशिकाएं ही शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करती हैं। इसलिए आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है क्योंकि हीमोग्लोबिन ही फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है। एनीमिया (Anemia) कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह कई बीमारियों की वजह जरूर बन सकता है। जीवनशैली के साथ आहार संबंधी आदतों में होने वाला बदलाव इस समस्या के मुख्य कारण के रूप में सामने आ रहा है। बढ़ते बच्चों, स्तनपान कराने वाली महिलाओं व बीमार व्यक्तियों में एनीमिया का खतरा ज्यादा होता है। विश्व की लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं, और हमारे देश की लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। कारण किडनी कैंसर किडनी से इरायथ्रोपोयॅटीन (Erythropoietin) नाम के हारमोन का उत्पादन होता है जो अस्थिमज्जा (Bone Marrow) को रेड-ब्लड सेल के निर्माण में मदद करता है, जिन लोगों को किडनी का कैंसर होता है उनके शरीर में इरायथ्रोपोयॅटीन (Erythropoieti) हारमोन का निर्माण नहीं होता है और इसकी वजह से रेड-ब्लड सेल्स का बनना भी कम हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन के जीन में बदलाव इस प्रकार के एनीमिया को सीकल सेल एनीमिया (Sickle Cell Anaemia) कहते हैं। असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण रेड ब्लड सेल्स सीकल यानी हंसिये के आकार के हो जाते हैं, सीकल सेल एनीमिया के कई प्रकार होते हैं जिनका असर अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग तरीके से होता है। थैलैसीमीयाथैलैसीमीया आनुवांशिक एनीमिया होता है, इस प्रकार के एनीमिया में हीमोग्लोबिन अपेक्षित मात्रा में बनने के बजाय कम या ज्यादा बनने लगता है। विटामीन बी-12 की कमीशरीर में विटामीन बी-12 की कमी से परनीसीयस एनीमिया होने की संभावना होती है। परनीसीयस एनीमिया ज़्यादातर शुद्ध शाकाहारी व्यक्तियों को और लंबे

व़क्त से शराब का सेवन करने वालों को होता है। रक्तस्राव से होने वाला एनीमिया माहवारी के दिनों में अत्यधिक स्राव, किसी चोट या घाव से स्राव, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर, कोलन कैंसर इत्यादि में धीरे-धीरे ख़ून लगातार रिसने से एनीमिया हो सकता है। लंबे समय से बीमार होने पर किसी भी प्रकार की दीर्घकालिक बीमारी से एनीमिया हो सकता है।

लक्षण आंखें पीली हो जाना कमजोरी और थकावट महसूस होना चक्कर आना छाती में दर्द होना एवं सीने में ऐठन होना त्वचा व नाखूनों का पीला होना लेट के उठने पर आँखों के सामने अन्धेरा छा जाना सांस फूलना सिर दर्द रहना हाथों और पैरों का ठंडा होना हृदय की धड़कन तेज या असामान्य होनापालक (Spinach) पालक में भरपूर लौह तथा विटामिन बी 12 होता है। इसके साथ ही पालक फोलिक एसिड (Folic Acid) का भी उच्च स्रोत है। ऐसे में पालक खाने से खून की कमी पूरी होती है। उपचार के लिए पालक का सूप बनाकर, या पालक का साग आदि को अपने रोज के खाने में शामिल करना चाहिए। अनार (Pomegranate)अनार शरीर में हीमोग्लोबिन (Haemoglobin) को बहुत तेजी से बढ़ाता है। अनार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा होती है। इसमें आयरन और कैल्शियम भी होता है। यह खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को तेजी से बढ़ाकर रक्त संचार को ठीक रखता है। एनीमिया के उपचार के लिए सुबह खाली पेट अनार खाएं और रोजाना अनार का जूस पीएं।टमाटर (Tomato)शरीर के लिए बहुत ज्यादा आयरन की मात्रा लेने के साथ ही यह भी जरूरी है कि आयरन को आपका शरीर सोखे। इसमें टमाटर अहम भूमिका निभाता है। रोजाना एक से दो कच्चे टमाटर जरूर खाएं। एक गिलास टमाटर का रस भी रोज पीएं और खाना बनाने और सलाद में भी टमाटर का भरपूर उपयोग करें।खजूर (Dates) खजूर भी आयरन बहुत अच्छा स्रोत है। सौ ग्राम खजूर में 90 मिलीग्राम आयरन की मात्रा होती है। दो खजूर को एक कप दूध में रात भर के लिए छोड़ दें। इन खजूर को सुबह खाली पेट चबा चबाकर खाएं। बचे हुए दूध को भी पी लें। खजूर को गरम पानी में दो या तीन घंटों के लिए भिगाकर उस पानी को पीना भी फायदेमंद होता है। जिन लोगों को लेक्टोज (lectose) से एलर्जी है और दूध नहीं ले सकते, उनके लिए यह बेहतर तरीका है।किशमिश (Kishmish) किशमिश भी एनीमिया की बेहद अच्छी घरेलू दवा है। किशमिश में आयरन, प्रोटीन, फाइबर, सोडियम जैसे उच्च पोषक तत्व होते हैं। उपचार के लिए एक कप पानी में 10 से 15 किशमिश रातभर के लिए भिगा दें। सुबह इन किशमिश को शहद मिलाकर खा लें और बचे हुए पानी को पी लें।शहद (Honey) शहद भी लौह और विटामिन बी 12 का उच्च स्रोत है। शहद को रोजाना खाने से भी शरीर में एनीमिया की कमी पूरी होती है। शहद को फलों में मिलाकर, दूध में डालकर या चीनी की जगह शहद इस्तेमाल करके भी रक्त की कमी पूरी की जा सकती है। बचाव एनीमिया ज्यादातर पौष्टिक आहार लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ प्रकार के एनीमिया में अलग-अलग तरह से उपचार कराने पड़ते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है डॉक्टरी परामर्श। खून की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले खाने में हरी सब्जियां (पालक, मेथी), फल व सलाद की मात्रा बढ़ानी चाहिए। सूखे मेवे जैसे खजूर, बादाम और किशमिश का खूब प्रयोग करना चाहिए। इसमें आयरन की पर्याप्त मात्रा होती है। फल जैसे खजूर, तरबूज, सेब, अंगूर, किशमिश और अनार खाने से खून बढ़ता है। अनार खाना एनीमिया (Fruits in Anemia) में काफी फायदा करता है ■

अर्थव्यवस्था को नई दिशा देती खेती किसानी

एक बात अब साफ हो गई है कि दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था को खेती किसानी ही नई दिशा दे सकती है। कोरोना लॉकडाउन और रूस-यूक्रेन युद्ध ने दो बातें साफ कर दी हैं कि औद्योगिकीकरण के बावजूद खेती किसानी की अपनी अहमियत है। जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान देश-दुनिया के लोगों का बड़ा सहारा खेती किसानी ही बनी, ठीक उसी तरह से भुखमरी से जूझते देशों के साथ ही समग्र विश्व की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार खेती किसानी रह गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि औद्योगिकीकरण समय की मांग है पर पिछले कुछ दशकों से औद्योगिकरण के नाम पर खेती किसानी की जिस तरह से उपेक्षा हुई उसका परिणाम रहा कि गांव उजड़ते गए और शहर गगनचुंबी इमारतों में तब्दील होते गए। इसके साथ ही उद्योग धंधों की प्राथमिकता के चलते कृषि क्षेत्र पर अपेक्षित ध्यान भी नहीं दिया गया। यह तो अन्नदाता की मेहनत का परिणाम रहा है कि देश में खाद्यान्नों के भण्डार भरे हैं।

कोरोना लॉकडाउन के कारण जब सबकुछ थम-सा गया उस समय में सबसे बड़ा सहारा खाद्यान्नों से भरे यह गोदाम ही रहे हैं। लोगों की एकमात्र आवश्यकता रसोई की सामग्री की उपलब्धता रही और इसमें सरकार पूरी तरह से सफल रही। आज अर्थशास्त्री एक बार फिर यह कहने लगे हैं कि यदि अर्थव्यवस्था को उबारना है तो इसके लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। सरकार भी अब कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान देने लगी है। यही कारण है कि लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो पैकेजों का दौर चला उसमें कृषि को खास महत्व दिया गया। कृषि क्षेत्र के प्रभाव को हमें दो तरह से समझना होगा। पहला यह कि कोरोना के चलते लॉकडाउन के हालातों और रोजगार ठप्प होने की स्थिति में लोगों को अनाज, दाल आदि उपलब्ध कराना ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए तो दूसरी और किसानों के हाथ में भी पूंजी का आना जिससे वे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सके। केन्द्र हो या राज्य सरकारें सभी इस दिशा में आगे बढ़ी हैं। यह समय की मांग भी है तो आवश्यकता भी। लॉकडाउन के दौरान देश के करीब 80 करोड़ लोगों तक गेहूं, चांवल, दाल आदि मुफ्त उपलब्ध कराया गया। देश के कई राज्यों में आज भी गरीबों और

साधनहीन लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में राशन सामग्री का वितरण कर लोगों को दो जून की रोटी उपलब्ध कराने की बड़ी पहल अन्नदाता की मेहनत का ही परिणाम है।

लॉकडाउन के दुष्परिणामों से या यों कहे कि बंदिशों से कृषि क्षेत्र को बचाये रखा जा सका तो इस क्षेत्र को जल्दी राहत देकर बचाया गया। इससे फसल की कटाई से लेकर मण्डियों में खरीद तक का मजबूत नेटवर्क प्रभावी रहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में सीधे किसानों के खातों में पैसा गया है इसका सीधा-सीधा लाभ किसानों को हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य संगठन द्वारा दुनिया के देशों को बार-बार खाद्यान्न संकट की चेतावनी दी जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव आने लगा है। असामयिक वर्षा, अतिवृष्टि और अनावृष्टि आम होती जा रही है। अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक वर्षा जहां आम होती जा रही है वहीं समुद्री तूफानों की रफ्तार बढ़ी है। जंगलों में आग लगने लगी है। रही सही कमी रूस यूक्रेन युद्ध ने कर दी है और इसके चलते खाद्यान्न संकट और एक देश से दूसरे देश पहुंचाने की समस्या गंभीर हो गई है। या यों कहें कि खाद्यान्नों का आयात निर्यात प्रभावित हो रहा है। श्रीलंका का प्रयोग सबके सामने है जहां जैविक खेती के निर्णय ने गंभीर संकट ला दिया और सरकार का तख्ता पलट गया। दरअसल दुनिया के देशों में खाद्य सामग्री के भावों में जिस तरह से तेजी आ रही है वह अपने आप में गंभीर समस्या है।

पिछले दिनों हमारे देश में सरकार ने किसानों के लिए राहतों की घोषणाएं की हैं। इसमें एक देश-एक मण्डी, तिलहन, दलहन, आलू प्याज आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम के नियंत्रण से मुक्त करने और कॉन्ट्रेक्ट खेती आदि प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान रेल को हरी झण्डी दिखाई तो राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राहत की घोषणाएं, सहकारी समितियों को गौण मण्डी का दर्जा देकर किसानों को अपनी उपज बेचने के अधिक व स्वतंत्र अवसर जैसी सुविधाएं दी हैं। इससे निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र को डोज मिलेगी पर अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। खेती किसानी के महत्व को देखते हुए ही पिछले दिनों सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का संजाल विकसित करने पर जोर देते हुए रोड़ मेप दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का एकमात्र सफल मॉडल सहकारिता ही है। इसी बात को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने समझा है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से देश के कोने कोने से मजदूरों-प्रवासियों ने पैदल ही सैंकड़ों मील की यात्रा कर गांव की ओर पलायन किया और जिस तरह के चित्र मीडिया के माध्यम से सामने आया उससे एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सरकार को अब गांव आधारित और खासतौर से कृषि, सह कृषि और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की ओर भी खास ध्यान देना होगा। जिस तरह से खेती में आधुनिक तकनीक के प्रयोग से पशुपालन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है उस नीति में भी अब बदलाव की आवश्यकता हो गई है। पशुपालन से किसानों की अतिरिक्त आय उनकी माली हालात को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है वहीं जैविक खेती या परंपरागत खेती को बढ़ावा देते हुए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम की जा सकती है। इस दिशा में सरकार को तेजी से आगे आना ही होगा।

हालांकि आर्थिक विश्लेषक मानने लगे हैं कि खेती ही अर्थव्यवस्था को जीवन दान दे सकती है। यही कारण है कि मानसून की अच्छी बरसात के चलते खरीफ फसल से बहुत आशा लगाई जा रही है। माना जा रहा है कि खरीफ में अधिक उत्पादन होगा और इससे अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि किसानों का भला होगा तो केवल दीर्घकालीन सुधार कार्यों से। उसे अच्छा बीज मिले, फसलोत्तर गतिविधियां वैज्ञानिक हों, मूल्य संवर्द्धन के लिए कृषि आधारित उद्योग लगे, भण्डारण खासतौर से कोल्ड स्टोरेज की चैन बने, कोल्ड स्टोरेज युक्त कंटेनर उपलब्ध हों ताकि उसकी उपज का सही मूल्य मिल सके। सबसे ज्यादा जरूरी है कि कृषि उपज के सरकारी मूल्यों की घोषणा समय पर व युक्तिसंगत हो और फिर फसल तैयार होते ही उसकी खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित हो। किसान को सड़कों पर अपनी उपज फेंकने के हालात किसी भी हालत में नहीं आने चाहिए। सरकार को ऐसा रोडमेप बनाना होगा जो उत्पादकता और आय बढ़ाने वाला हो। ■

जाति की जंजीरें..!

ब्यूरो डेस्क

जाति की जंजीरें: आज़ादी के बाद भी मानसिक गुलाटी। आस्था पेशाब तक पिला देती है, जाति पानी तक नहीं पीने देती। कैसे लोग अंधभक्ति में बाबा की पेशाब को "प्रसाद" मानकर पी सकते हैं, लेकिन जाति के नाम पर दलित व्यक्ति के छूने मात्र से पानी अपवित्र मान लिया जाता है। इन समस्याओं की जड़ें धर्म, राजनीति, शिक्षा और मीडिया की भूमिका में छिपी हैं। शिक्षा में विवेक की कमी, मीडिया की चुप्पी, धर्मगुरुओं की मनमानी और जातिवादी मानसिकता समाज को पिछड़ेपन की ओर ढकेल रही है। यह सवाल उठाता है कि यदि आस्था किसी बाबा की पेशाब को 'पवित्र' मान सकती है, तो एक दलित का पानी 'अपवित्र' कैसे हो सकता है...?

भारत, जिसे आध्यात्मिकता और विविधता का देश कहा जाता है, अपने भीतर विरोधाभासों का एक ऐसा संसार छुपाए बैठा है जो कभी-कभी चौंका देता है। एक ओर हम विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक और सांस्कृतिक परतों में आज भी मध्ययुगीन सोच जड़ें जमाए बैठी है। एक ही समाज में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जहां लोग किसी बाबा के चरणामृत को 'अमृत' मानकर पी जाते हैं, यहां तक कि गोमूत्र और गोबर को औषधि बताकर उसका सेवन करते हैं; और उसी समाज में एक दलित व्यक्ति के हाथ का पानी पीना 'पाप' मान लिया जाता है। यही वह विडंबना है जिसे इस तीखे वाक्य ने पूरी ताकत से उजागर किया है—"आस्था पेशाब तक पिला देती है, जाति पानी तक नहीं पीने देती।" यह पंक्ति महज़ एक व्यंग्य नहीं, बल्कि भारतीय समाज की गहराई से जमी हुई दो बड़ी बीमारियों की पहचान है—एक है अंधविश्वास में डूबी आस्था और दूसरी है जातिगत भेदभाव। दोनों ही एक हद तक इंसानियत, तर्कशक्ति और समानता के मूल सिद्धांतों को चुनौती देते हैं।

आस्था: श्रद्धा और मूर्खता के बीच की पतली रेखा

आस्था किसी भी समाज की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रीढ़ होती है। यह इंसान को एक उद्देश्य देती है, उसे नैतिकता और आत्मबल प्रदान करती है। लेकिन जब यही आस्था तर्क, विज्ञान और मानवाधिकारों की सीमा लांघकर अंधश्रद्धा में बदल जाती है, तब वह खतरनाक रूप ले लेती है। भारत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां धर्मगुरुओं ने अपने अनुयायियों को गोमूत्र पीने, मल-मूत्र का सेवन करने, या स्वयं को 'भगवान' घोषित कर देने जैसे कृत्य करवाए और लोग आंख मूंदकर उनका पालन करते रहे। एक बाबा द्वारा 'चमत्कारी जल' के नाम पर अपनी पेशाब पिलाने की खबरें भी समय-समय पर सामने आती रही हैं। श्रद्धालु इसे 'आशीर्वाद' मानकर पीते हैं, और मीडिया जब इन घटनाओं पर सवाल उठाती है, तो आरोप लगाया जाता है कि वह धर्म का अपमान कर रही है। यह कैसी आस्था है जो इंसान को अपनी सोच और विवेक को पूरी तरह त्यागने को विवश कर देती है? यह कैसी श्रद्धा है जो सवाल उठाने वालों को अपराधी बना देती है?

जाति: एक आधुनिक समाज में मध्यकालीन सोच

अब बात करें उस दूसरी बड़ी सामाजिक बीमारी की—जातिवाद की। भारत में जाति एक ऐसी संरचना है जो जन्म के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक हैसियत, पेशा, अधिकार और यहां तक कि जीवन-मरण के अवसर भी तय करती है। भारतीय संविधान ने भले ही जातिवाद को गैरकानूनी घोषित कर दिया हो, लेकिन सामाजिक मानसिकता में इसकी जड़ें आज भी उतनी ही गहरी हैं। आज भी देश के कई हिस्सों में दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता, उनके लिए अलग कुएं या नल होते हैं, स्कूलों में उनके बच्चों को अलग बैठाया जाता है, और उनके स्पर्श मात्र से वस्तुएं 'अपवित्र' मानी जाती हैं। हाथ से मैला उठाने जैसी अमानवीय प्रथा आज भी समाप्त नहीं हुई है। ऐसे उदाहरण रोज़ सामने आते हैं जब दलित युवक को ऊंची जाति की लड़की से प्रेम करने के लिए मार दिया जाता है, या जब किसी गांव में सिर्फ इस वजह से उनके घरों में आग लगा दी जाती है कि उन्होंने 'मर्यादा' लांघी। यह कितना त्रासद है कि वही समाज जो गोमूत्र को औषधि मान सकता है, वह एक इंसान के छूने मात्र से पानी को अपवित्र मानता है।

विरोधाभास की जड़ें

इस विरोधाभास की जड़ें कहीं और नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संरचना में छिपी हुई हैं। धर्म के नाम पर आस्था को हथियार बनाकर लोगों की सोच को नियंत्रित किया गया। धर्मग्रंथों की मनमानी व्याख्याओं के ज़रिए एक वर्ग को 'ऊंचा' और दूसरे को 'नीचा' साबित किया गया। जो सवाल उठाए, वह 'धर्म विरोधी' करार दे दिया गया।

राजनीति ने भी इस व्यवस्था को खूब पोषित किया। जातियों को वोट बैंक में बदल दिया गया। आरक्षण के नाम पर नफरत फैलाई गई, लेकिन जातिगत अत्याचार को खत्म करने के लिए न ठोस प्रयास किए गए, न इच्छाशक्ति दिखाई गई। आस्था के नाम पर जनता को भावनात्मक रूप से बांधा गया, और वैज्ञानिक सोच को 'पश्चिमी विचारधारा' बताकर नकार दिया गया।

शिक्षा और विवेक की कमी

शिक्षा वह उपकरण है जो समाज को तर्कशील और न्यायप्रिय बनाता है। लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था में तर्क और मानवाधिकार की शिक्षा बहुत सीमित है। हम बच्चों को विज्ञान पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी सोच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं भरते। हम उन्हें नैतिक शिक्षा देते हैं, लेकिन जातिवाद और सामाजिक न्याय के सवालों पर चुप रहते हैं। जब बच्चा स्कूल में यह देखता है कि उसके सहपाठी को 'चमार' या 'भंगी' कहा जा रहा है, जब शिक्षक ही छात्रों से जाति पूछते हैं, तो यह सोच उसकी चेतना में गहराई तक बैठ जाती है। यही बच्चा बड़ा होकर वही भेदभाव करता है, और एक बार फिर वह दुष्चक्र शुरू हो जाता है।

मीडिया और समाज का दोगलापन

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जब बात जातिवाद या अंधविश्वास की आती है, तो उसका रुख या तो बेहद सतही होता है या पूरी तरह से चुप्पी ओढ़ लेता है। बाबाओं के चमत्कारों को वह 'मनोरंजन' के नाम पर दिखाता है, लेकिन किसी दलित की हत्या पर सिर्फ दो मिनट की रिपोर्ट चलाकर बात खत्म कर देता है। वह जानबूझकर ऐसे मुद्दों से बचता है जो उसे किसी 'विशेष वर्ग' से नाराज़ कर सकते हैं। वहीं समाज भी अपनी सुविधानुसार संवेदनशीलता चुनता है। गोमूत्र बेचने वाले को 'आधुनिक

ऋषि' कहा जाता है, लेकिन मैनहोल की सफाई करते मजदूर की मौत पर कोई आवाज़ नहीं उठती।

—— तेरी क्या है जात ——

बाबा बोले मूत्र पिएँ, पीते श्रद्धावान।
मगर दलित का जल बने, छूते ही अपमान॥
नेत्र मूँद कर मानते, बाबा को भगवान।
तर्क बिना की आस्था, ले लेती है जान॥
ठहर जन्म से जो गया, नीचे उसका मान।
कर्म न देखा जात बस, कैसी यह पहचान॥
पढ़े-लिखे भी पूछते, तेरी क्या है जात।
ज्ञान बिना जब सोच हो,
व्यर्थ लगे सब बात॥
छपते चमत्कार बहुत, बन जाते सौगात।
दलित मरे तो छप सके, दो लाइन की बात॥
वोट हेतु बस जातियाँ, गढ़ते सभी विधान।
सत्ता की यह राक्षसी, निगल रही इंसान॥
धर्म वही जो प्रेम दे, करुणा जिसका मूल।
जो बांटे पाखंड है, मानवता पर धूल॥
एक ओर चाँद चूमता, विज्ञान करे बात।
दूजी ओर दलित मरे, मंदिर से हो घात॥
विवेकशील शिक्षा बने, तर्कशील अरमान।
निकाले अंधकूप से, नवचेतन का गान॥
धर्म वही जो जोड़ दे, तोड़े ना इंसान।
जात-पात से मुक्त हो, हो सबका सम्मान॥
जाति-पांति को छोड़कर,
बढ़े मनुज का मान।
आधार कर्म हो जहाँ, सौरभ सच्चा ज्ञान॥

क्या है समाधान?

तर्कशील शिक्षा का विस्तार: स्कूलों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक न्याय पर आधारित पाठ्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों को बचपन से यह सिखाना ज़रूरी है कि आस्था का मतलब अंधश्रद्धा नहीं होता, और हर इंसान समान है। सख्त कानून और उनका क्रियान्वयन: जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ बने कानूनों को सिर्फ कागज़ पर नहीं, ज़मीन पर भी लागू करना होगा।

दोषियों को सज़ा मिले, तभी समाज में बदलाव संभव है। मीडिया की ज़िम्मेदारी: मीडिया को इस विषय पर ईमानदार विमर्श शुरू करना चाहिए। दलितों के मुद्दों, जातिगत अन्याय और अंधविश्वास के खिलाफ सशक्त रिपोर्टिंग ज़रूरी है। धार्मिक संस्थाओं में सुधार: धर्मगुरुओं को अपने अनुयायियों को विज्ञान और सामाजिक समानता का संदेश देना चाहिए। अगर धर्म में परिवर्तन नहीं होगा, तो समाज में भी नहीं होगा। सिविल सोसायटी और युवाओं की भागीदारी: सामाजिक संगठनों, छात्रों और जागरूक नागरिकों को इस व्यवस्था के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठानी होगी। सोशल मीडिया को एक सशक्त माध्यम बनाकर जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जा सकता है।

क्या हम सच में आधुनिक हो पाए हैं?

भारत जब चंद्रमा पर पहुंचने की उपलब्धि का जश्न मना रहा होता है, तभी किसी गांव में एक दलित को मंदिर में प्रवेश करने पर पीट-पीट कर मार दिया जाता है। जब एक ओर सरकारी अभियान 'स्वच्छ भारत' का नारा देते हैं, वहीं दूसरी ओर हजारों सफाईकर्मी बिना सुरक्षा के गटर में उतरकर दम तोड़ते हैं। और जब एक ओर लोग बाबा की पेशाब को 'प्रसाद' मानकर पीते हैं, उसी समय एक दलित का छुआ पानी 'गंदा' मान लिया जाता है। यह विरोधाभास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विकास सिर्फ इमारतें, मेट्रो और मोबाइल नेटवर्क तक सीमित है, या इसमें सोच, समानता और इंसानियत भी शामिल है? आस्था का स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वह इंसानियत को कुचलती है, तो वह किसी काम की नहीं। जाति की संरचना अगर किसी को उसका मानवाधिकार नहीं देती, तो वह टूटनी ही चाहिए। इसलिए आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम इस पाखंड को पहचानें और उसके खिलाफ बोलें। आस्था अगर पेशाब तक पिला सकती है, तो समाज को इतना संवेदनशील और तर्कशील बनाना होगा कि जाति के नाम पर पानी से इनकार न किया जाए। इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म और चरित्र से हो—यही असली धर्म है, यही सच्ची आस्था। ■

वायु प्रदूषण नौनिहालों की ले रहा जान

दिल्ली ही नहीं देश के अन्य बड़े शहरों में भी प्रदूषण से हवा जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। दिल्ली सहित देश के चार बड़े शहरों में कराए गए एक सर्वे में यह बात सामने भी आई है...

ब्यूरो डेस्क

पूर्वी एशियाई देशों में प्रदूषित हवा का असर लोगों के जीवन पर हो रहा है। वायु प्रदूषण की वजह से यहां हर दिन पांच साल से कम उम्र के 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इन दिनों वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। खराब हालात की वजह से स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं।

यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट में पूर्वी एशियाई देशों और प्रशांत क्षेत्र से जुड़े इलाकों में वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि वायु प्रदूषण से जुड़े कारणों से साल 2021 में इन इलाकों में हर दिन पांच साल से कम उम्र के 100 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान गंवाई। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन इलाकों में रहने वाले 50 करोड़ बच्चे ऐसे देशों में रहते हैं जहां वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है।

खाना बनाने और गर्मी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन से होने वाला घरेलू वायु प्रदूषण पांच साल से कम उम्र के आधे से ज्यादा बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है। 32 करोड़

से ज्यादा बच्चे ऐसे देशों में रहते हैं जहां सालाना पीएम2.5 का औसत स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा सुझाए गए स्तर से पांच गुना ज्यादा है।

37 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे देशों में रहते हैं जहां नाइट्रोजन ऑक्साइड खतरनाक स्तर पर है। यूनिसेफ की पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक जून कुनूगी कहती हैं कि हर सांस कीमती है, लेकिन बहुत से बच्चों के लिए यह नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है। उन्होंने कहा, 'जब उनका शरीर और दिमाग विकसित हो रहा होता है, तब वो ऐसी हवा में सांस लेते हैं जो उनके विकास को प्रभावित करती है।' वायु प्रदूषण पूर्वी एशियाई देशों और प्रशांत क्षेत्र में पांच साल के कम उम्र के लगभग चार में से एक बच्चे की मौत का कारण है और उनके जीवन और विकास को प्रभावित कर सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार बच्चों पर प्रदूषण के असर की शुरूआत गर्भ से ही हो जाती है, जिससे समय से पहले प्रसव और कम वजन के साथ पैदा होने वाली बच्चों जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। बच्चे तेजी से सांस लेते हैं, इसलिए वे प्रदूषकों के संपर्क में आने की वजह से अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से डायबिटीज और दिल से जुड़ी कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता बोझः वायु प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य से ज्यादा पहले से बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर डालता है।

इससे न सिर्फ उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित होती है बल्कि बीमारी की वजह से स्कूलों में अनुपस्थिति, मस्तिष्क का विकास रुकने जैसी तमाम समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बीमार बच्चों की देखभाल का खर्च माता-पिता की आय को प्रभावित करता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2019 में, वायु प्रदूषण की वजह से पूर्वी एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में लोगों की असमय मौत और बीमारियों की वजह से होने वाला खर्च वहां की जीडीपी का 9.3 फीसदी था, जो 25 खरब डॉलर से भी ज्यादा है।

खौफ का वो लम्हा...

मंजेश कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद पहुंचे और एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दुर्घटना स्थल का दौरा किया, जिसमें पिछले दिन 241 लोगों की जान चली गई थी, जो हाल के वर्षों में सबसे घातक हवाई दुर्घटनाओं में से एक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अहमदाबाद पहुंचे और एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दुर्घटना स्थल का दौरा किया, जिसमें पिछले दिन 241 लोगों की जान चली गई थी, जो हाल के वर्षों में सबसे घातक हवाई दुर्घटनाओं में से एक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से निकलते हुए देखा गया, जहां उन्होंने गुरुवार को एयर इंडिया विमान दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 297 हो गई है। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि इस त्रासदी में केवल एक यात्री ही जीवित बचा है। मृतकों में 229 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य थे। इसके अलावा, विमान एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उस समय वहां मौजूद 56 लोगों की मौत हो गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने सभी को स्तब्ध कर दिया है और इतने आकस्मिक और हृदय विदारक तरीके से इतने अधिक लोगों की मौत शब्दों से परे है। मोदी ने 'एक्स' पर अपने शोक संदेश में यह बात कही। उन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और हादसे में जीवित बचे एकमात्र शख्स और घायलों से अस्पताल में मुलाकात की।

उन्होंने कहा, ''हम अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से स्तब्ध हैं। इतने आकस्मिक और हृदय विदारक तरीके से इतने अधिक लोगों की मौत शब्दों से परे है। सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं।''

मोदी ने कहा, ''हम उनका दर्द समझते हैं और यह भी जानते हैं कि उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ है, वह आने वाले कई वर्षों तक महसूस किया जाएगा। ओम शांति।'' अहमदाबाद में बृहस्पतिवार को एअर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी 241 लोगों की मौत हो गई।

अब अहमदाबाद में एअर इंडिया के विमान की भीषण दुर्घटना में 270 लोगों की मौत के चार दिन बाद, अब तक डीएनए मिलान के माध्यम से 87 मृतकों की पहचान कर ली गई है और 47 लोगों के शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

जांचकर्ताओं ने दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया विमान से कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) बरामद कर लिया है, जो पिछले सप्ताह हुई घातक दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। लंदन जाने वाला एयर इंडिया विमान, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, गुरुवार को पश्चिमी भारतीय शहर अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कम से कम 270 लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश यात्री थे। अब अहमदाबाद में एअर इंडिया के विमान की भीषण दुर्घटना में 270 लोगों की मौत के चार दिन बाद, अब तक डीएनए मिलान के माध्यम से 87 मृतकों की पहचान कर ली गई है और 47 लोगों के शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी मृतकों की पहचान करने के लिए डीएनए परीक्षण कर रहे हैं क्योंकि 12 जून को विमान दुर्घटना में कई लोग इतनी बुरी तरह जल गए थे कि उनके शव पहचाने नहीं जा सके। अतिरिक्त सिविल अधीक्षक डॉ

रजनीश पटेल ने संवाददाताओं को बताया, ''अब तक, 87 डीएनए नमूनों का मिलान किया गया है, और 47 लोगों के शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। ये मृतक गुजरात के विभिन्न हिस्सों, जैसे भरूच, आनंद, जूनागढ़, भावनगर, वडोदरा, खेड़ा, मेहसाणा, अरवल्ली और अहमदाबाद जिलों के रहने वाले थे।''

गत बृहस्पतिवार को दोपहर 1.39 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

लंदन जाने वाले इस विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। दुर्घटना में 29 अन्य लोगों के मारे जाने की भी खबर है, जिनमें पांच एमबीबीएस छात्र शामिल थे।

एअर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद अब तक कुल 270 शव अहमदाबाद सिविल अस्पताल में लाए गए हैं। अस्पताल के चिकित्सकों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने पहले मरने वालों की संख्या 265 बताई थी। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 24 घंटे में, शहर की दमकल टीम ने विमान दुर्घटनास्थल से एक शव और शरीर के कुछ अंग बरामद किए हैं।

बीजे मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. धवल गमेती ने कहा, विमान दुर्घटनास्थल से अब तक लगभग 270 शव सिविल अस्पताल लाए गए हैं। डीएनए नमूनों का मिलान करके शवों की शिनाख्त की प्रक्रिया अभी जारी है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव रिश्तेदारों को सौंप दिए जाएंगे।

अहमदाबाद अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (एएफईएस) ने मेघाणीनगर क्षेत्र में विमान दुर्घटना स्थल से पिछले 24 घंटे में मानव शरीर के कुछ अंग और एक शवबरामद किया है। बृहस्पतिवार दोपहर अहमदाबाद से 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रहा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर (एआई 171) विमान सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद मेघाणीनगर में एक मेडिकल हॉस्टल और उसके कैंटीन परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर (एआई171) शहर के सिविल अस्पताल और बीजे मेडिकल कॉलेज में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें

आग लग गई। एयर इंडिया के अनुसार, 230 यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, सात पुर्तगाली और एक कनाडाई थे। अन्य 12 में दो पायलट और 10 चालक दल के सदस्य थे।

टाटा समूह ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक पीड़ित के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। 242 यात्रियों और चालक दल को ले जा रहा एयर इंडिया का विमान गुरुवार दोपहर उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर (एआई171) शहर के सिविल अस्पताल और बीजे मेडिकल कॉलेज में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। एयर इंडिया के अनुसार, 230 यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, सात पुर्तगाली और एक कनाडाई थे। अन्य 12 में दो पायलट और 10 चालक दल के सदस्य थे।

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, "हम घायलों के चिकित्सा व्यय को भी वहन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सभी आवश्यक देखभाल और सहायता मिले। इसके अतिरिक्त, हम बी.जे. मेडिकल के छात्रावास के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेंगे।"

बयान में कहा गया, "एयर इंडिया फ्लाइट 171 से जुड़ी दुखद घटना से हम बहुत दुखी हैं। इस समय हम जो दुख महसूस कर रहे हैं, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और जो घायल हुए हैं।" बयान में कहा गया, "एयर इंडिया फ्लाइट 171 से जुड़ी दुखद घटना से हम बहुत दुखी हैं। इस समय हम जो दुख महसूस कर रहे हैं, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और जो घायल हुए हैं।''

टाटा समूह के चेयरमैन ने यह भी आश्वासन दिया कि कंपनी इस दुखद घटना से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। दुर्घटना के बाद अहमदाबाद स्थित एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा कि दोहरे इंजन वाले विमान के पायलट ने उड़ान भरने के तुरंत बाद दोपहर 1:39 बजे 'मेडे' संकट कॉल जारी किया, जो पूर्ण आपातकाल को दर्शाता था। इस बीच, विमान के ब्लैक बॉक्स की खोज जारी है, जो यह समझने के लिए आवश्यक है कि अंतिम महत्वपूर्ण क्षणों में क्या हुआ था। ■

किशोरों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति गंभीर चुनौती

भारतीय बच्चों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति एवं क्रूर मानसिकता चिन्ताजनक है, नये भारत एवं विकसित भारत के भाल पर यह बदनुमा दाग है। पिछले कुछ समय से स्कूली बच्चों में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति निश्चित रूप से डरावनी, मर्मांतक एवं खौफनाक है। चिंता का बड़ा कारण इसलिए भी है क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास की नींव रखी जाती है, उसी उम्र में कई बच्चों में आक्रामकता एवं क्रूर मानसिकता घर करने लगी है और उनका व्यवहार हिंसक होता जा रहा है। कैथल जनपद के गांव धनौरी में दो किशोरों की निर्मम एवं क्रूर हत्या की हृदयविदारक घटना न केवल उद्वेलित एवं भयभीत करने वाली है बल्कि चिन्ताजनक है। चौदह-पंद्रह साल के दो किशोरों की गला रेतकर हत्या कर देना और वह भी उनके हमउम्र साथियों द्वारा, हर संवेदनशील इंसान को हिला देने वाली डरावनी एवं खैफनाक घटना है, जो किशोरों में पनप रहे हिंसक बर्ताव एवं हिंसक मानसिकता का घिनौना एवं घातक रूप है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई-लिखाई और खेलकूद में व्यस्त रहना चाहिए, उसमें उनमें बढ़ती आक्रामकता, हिंसा एवं क्रूरता एक अस्वाभाविक और परेशान करने वाली बात है। जाहिर है दसवीं-ग्यारहवीं के छात्रों की क्रूर हत्या हमारे समाज में बढ़ती संवेदनहीनता को भी दर्शाती है। ऐसी कई अन्य घटनाओं में स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे ने अपने सहपाठी पर चाकू या किसी घातक हथियार से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। अमेरिका की तर्ज पर भारत के बच्चों में हिंसक मानसिकता का पनपना हमारी शिक्षा, पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना पर कई सवाल खड़े करती है।

जैसाकि घटना से संबंधित तथ्यों में बताया गया कि हत्या में शामिल युवक धनौरी गांव के ही थे और कुछ दिन पहले किशोरों को धमकाने उनके घर आए थे। मारे गए किशोरों पर हत्या आरोपियों ने आरोप लगाया था कि वे उनकी बहनों से छेड़खानी करते थे। निश्चय ही ऐसे छेड़खानी के कथित आरोप को नैतिक दृष्टि से अनुचित ही कहा जाएगा, लेकिन उसका बदला हत्या कदापि नहीं हो सकती। यह दुखद है कि एक मृतक किशोर अरमान पांच बहनों का अकेला भाई था। घटना से उपजी त्रासदी से अरमान के परिवार पर हुए वज्रपात को सहज महसूस किया जा सकता है। उनके लिये जीवनभर न भुलाया जा सकने वाला दुख एवं संत्रास पैदा हुआ है। बड़ा सवाल है कि जिन वजहों से बच्चों के भीतर आक्रामकता एवं हिंसा पैदा हो रही है, उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? पाठ्यक्रमों का स्वरूप, पढ़ाई-लिखाई के तौर-तरीके, बच्चों के साथ घर से लेकर स्कूलों में हो रहा व्यवहार, उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों का दायरा, संगति, सोशल मीडिया या टीवी से लेकर सिनेमा तक उसकी सोच-समझ को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से

तैयार होने वाली उनकी मनःस्थितियों के बारे में सरकार, समाजकर्मी एवं अभिभावक क्या समाधान खोज रहे हैं। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा?

बहरहाल, इस हृदयविदारक एवं त्रासद घटना ने नयी बन रही समाज एवं परिवार व्यवस्था पर अनेक सवाल खड़े किये हैं। सवाल नये बन रहे समाज की नैतिकता एवं चरित्र से भी जुड़े हैं। निश्चित ही किसी परिवार की उम्मीदों का यूं कत्ल होना मर्मांतक एवं खौफनाक ही है। लेकिन सवाल ये है कि चौदह-पंद्रह साल के किशोरों पर यूं किन्हीं लड़कियों को छेड़ने के आरोप क्यों लग रहे हैं? पढ़ने-लिखने की उम्र में ये सोच कहां से आ रही है? क्यों हमारे अभिभावक बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं ताकि वे किसी की बेटी व बहन को यूं परेशान न करें? क्यों लड़कियों से छेड़छाड़ की अश्लील एवं कामूक घटनाएं बढ़ रही है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा का वह पक्ष उपेक्षित हो चला है, जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है? क्या शिक्षक छात्रों को सदाचारी व नैतिक मूल्यों का जीवन जीने की प्रेरणा देने में विफल हो रहे हैं? हत्या की घटना हत्यारों की मानसिकता पर भी सवाल उठाती है कि उन्होंने क्यों सोच लिया कि छेड़खानी का बदला हिंसा एवं क्रूरता से गला काटना हो सकता है? धनौरी की घटना के पूरे मामले की पुलिस अपने तरीके से जांच करेगी, लेकिन किशोर अवस्था में ऐसी घटना को अंजाम देने के पीछे बच्चे की मानसिकता का पता लगाना भी ज्यादा जरूरी है। दरअसल, दशकों तक बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों ने समाज एवं विशेषतः किशोर पीढ़ी में जिस अपसंस्कृति का प्रसार किया, आज हमारा समाज उसकी त्रासदी झेल रहा है। इसमें दो राय नहीं कि किशोरवय में राह भटकने का खतरा ज्यादा रहता है। अब तक हिन्दी सिनेमा से समाज के किशोरवय और युवाओं में गलत संदेश गया कि निजी जीवन में छेड़खानी ही प्रेम कहानी में तब्दील हो सकती है। हमारे टीवी धारावाहिकों की संवेदनहीनता ने गुमराह किया है। बॉक्स आफिस की सफलता और टीआरपी के खेल ने मनोरंजक कार्यक्रमों में ऐसी नकारात्मकता एवं हिंसक प्रवृत्ति भर दी कि किशोरों में हिंसक एवं अराजक सोच पैदा हुई। इंटरनेट के विस्तार और सोशल मीडिया के प्रसार से स्वच्छंद यौन व्यवहार का ऐसा अराजक एवं अनियंत्रित रूप सामने आया कि जिसने किशोरों व युवकों को पथभ्रष्ट एवं दिग्भ्रमित करना शुरू कर दिया। आज संकट ये है कि हर किशोर के हाथ में आया मोबाइल उसे समय से पहले वयस्क बना रहा है। जिस पर न परिवार का नियंत्रण है और न ही शिक्षकों का। 'मन जो चाहे वही करो' की मानसिकता वहां पनपती है जहां इंसानी रिश्तों के मूल्य समाप्त हो चुके होते हैं, जहां व्यक्तिवादी व्यवस्था में बच्चे बड़े होते-होते स्वछन्द हो जाते हैं। अर्थप्रधान दुनिया में माता-पिता के पास बच्चों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं बच पा रहा।

आज किशोरों एवं युवाओं को प्रभावित करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व नये-नये एप पश्चिमी अपसंस्कृति से संचालित हैं। इन पर अश्लीलता और यौन-विकृतियों वाले कार्यक्रमों का बोलबाला है।

ऐसे कार्यक्रमों की बाढ़ हैं जिनमें हमारे पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों में स्वच्छंद यौन व्यवहार को हकीकत बनाने का खेल चल रहा है। पारिवारिक एवं सामाजिक उदासीनता एवं संवादहीनता से ऐसे बच्चों के पास सही जीने का शिष्ट एवं अहिंसक सलीका नहीं होता। वक्त की पहचान नहीं होती। ऐसे बच्चों में मान-मर्यादा, शिष्टाचार, संबंधों की आत्मीयता, शांतिपूर्ण सहजीवन आदि का कोई खास ख्याल नहीं रहता। भौतिक सुख-सुविधाएं एवं यौनाचार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है। भारतीय बच्चों में इस तरह का एकाकीपन उनमें गहरी हताशा, तीव्र आक्रोश और विषैले प्रतिशोध का भाव भर रहा है। वे मानसिक तौर पर बीमार बन रहे हैं, वे आत्मघाती-हिंसक बन रहे हैं और अपने पास उपलब्ध खतरनाक एवं घातक हथियारों का इस्तेमाल कर हत्याकांड कर बैठते हैं।

ऑस्ट्रिया के क्लागेनफर्ट विश्वविद्यालय की ओर से किशोरों पर किए गए अध्ययन में पता चला है कि दुनिया भर में 35.8 प्रतिशत से ज्यादा किशोर मानसिक तनाव, अनिद्रा, अकारण भय, पारिवारिक अथवा सामाजिक हिंसा, चिड़चिड़ापन अथवा अन्य कारणों से जूझ रहे हैं। एकाकीपन बढ़ने से वे ज्यादा आक्रामक और विध्वंसक सोच की तरफ बढ़ने लगे हैं। मोबाइल व कथित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बह रहे नीले जहर से किशोर अराजक यौन व्यवहार एवं हिंसक प्रवृत्तियों की तरफ उन्मुख हुए हैं। किशोरों को समझाने वाला कोई नहीं है कि यह रास्ता आत्मघात का है। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व ब्रिटेन जैसे देश किशोरों को मोबाइल से दूर रखने हेतु कानून बना रहे हैं। हमारे देश में भी शीर्ष अदालत ने समय-समय पर ऐसी घटनाओं पर तल्ख टिप्पणियां की हैं। क्या इन दर्दनाक घटनाओं से हमारे अभिभावकों, समाज-निर्माताओं एवं हमारे सत्ताधीशों की आंख खुलेगी? बच्चों से जुड़ी हिंसा की इन वीभत्स एवं त्रासद घटनाओं से जिन्दगी सहम गयी है। हमें मानवीय मूल्यों के लिहाज से भी विकास एवं नयी समाज-व्यवस्था की परख करनी होगी। बच्चों के भीतर हिंसा मनोरंजन की जगह ले रही है। इसी का नतीजा है कि छोटे-छोटे स्कूली बच्चे भी अपने किसी सहपाठी की हत्या तक कर रहे हैं। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा?■

ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार है

मेथीदाना की चाय

अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है। चायपत्ती, चीनी और दूध की मदद से बनने वाली चाय को अक्सर सेहत के लिए काफी नुकसानदायक माना जाता है। लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए चाय का सेवन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप मेथी की चाय का सेवन करें। मेथी के बीजों से बनी इस चाय से आपकी सेहत को कई तरह के लाभ मिलते हैं। खासतौर से, अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है तो आपको मेथी की चाय का सेवन जरूर करना चाहिए। यह आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मददगार है। साथ ही साथ, ब्लड शुगर स्पाइक और क्रैश ना होने के कारण आपको अपना एनर्जी लेवल बनाए रखने में भी काफी मदद मिलती है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि मेथी की चाय ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में किस तरह मददगार है-

मेथी के बीजों में सॉल्यूबल फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। जिसका अर्थ है कि यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण को धीमा कर देते हैं। इससे आपको खाना खाने के बाद एकदम से ब्लड शुगर लेवल के स्पाइक होने की शिकायत नहीं होती है।

इंसुलिन सेंसेटिविटी में होता है सुधार

मेथी की चाय पीने से इंसुलिन सेंसेटिविटी में सुधार होता है। दरअसल, मेथी के बीजों में ट्राइगोनेलिन और 4-हाइड्रॉक्सीसोल्यूसीन जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं। ये कंपाउंड आपके शरीर द्वारा इंसुलिन का उपयोग करने के तरीके को बेहतर बनाते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करना अधिक आसान हो जाता है।

फाइबर से भरपूर

मेथी के बीजों में सॉल्यूबल फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। जिसका अर्थ है कि यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण को धीमा कर देते हैं। इससे आपको खाना खाने के बाद एकदम से ब्लड शुगर लेवल के स्पाइक होने की शिकायत नहीं होती है।

शरीर को इंसुलिन बनाने में करे मदद

मेथी की चाय पीना डायबिटीज रोगियों के लिए इसलिए भी लाभकारी माना गया है, क्योंकि मेथी के बीज आपके शरीर के इंसुलिन बनाने वाले अंग अर्थात् अग्न्याशय को अधिक इंसुलिन बनाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए, यह यह टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक है, जहां शरीर इंसुलिन को ठीक से नहीं बनाता या उपयोग नहीं करता है।

चीनी के अवशोषण को करे कम

जब आप मेथी की चाय पीते हैं, तो यह आपके शरीर द्वारा भोजन से अवशोषित की जाने वाली चीनी की मात्रा को धीमा कर देता है। जिससे ग्लूकोज लेवल स्टेबल रहता है और खाने के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल एकदम तेजी से नहीं बढ़ता है। ■

एक्सपर्ट ने बताया नेचुरली ब्राइट और ग्लोइंग हो जाएगी स्किन

न्यूट्रिशनिस्ट ने 5 ऐसी चीजों के बारे में बताया है, जिन्हें डाइट में शामिल करना होने वाली दुल्हन के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है।

शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे में अगर आप भी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है। गौरतलब है कि शादी हर किसी की लाइफ के सबसे खास दिनों में से एक होता है। ऐसे में अपने इस खास दिन पर हर कोई सबसे खूबसूरत दिखना चाहते है।

इसके लिए खासकर होने वाली दुल्हन महीनों पहले से ही पार्लर के चक्कर लगाना और तमाम तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देती हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ कर रही हैं, तो बता दें कि इन ट्रीटमेंट से अलग स्किन को नेचुरली ब्राइट और ग्लोइंग बनाने के लिए आप अपनी डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल भी कर सकती हैं।

इसके लिए हाल ही में पोषण विशेषज्ञ दीपशिखा जैन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट ने 5 ऐसी चीजों के बारे में बताया है, जिन्हें डाइट में शामिल करना होने वाली दुल्हन के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में-

एवोकाडो

लिस्ट में पहला नाम आता है एवोकाडो का। न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, 'एवोकाडो में ग्लूटाथिओन की अच्छी मात्रा मौजूद होती है, जो स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। ऐसे में आप रोज एक एवोकाडो खा सकती हैं।'

शकरकंद

सर्दी का मौसम आते ही बाजार में शकरकंद दिखना शुरू हो जाती हैं। वहीं, पोषण विशेषज्ञ इसे भी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद बताती हैं। दीपशिखा जैन के मुताबिक, शकरकंद में बीटा कैरोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट बेहद अच्छी मात्रा में होते हैं, जो स्किन पर डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन को कम करने में असर दिखाते हैं।'

नारियल पानी

अच्छी स्किन के लिए एक्सपर्ट रोज नारियल पानी पीने की सलाह देती हैं। इससे स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रखने में मदद मिलती है, जिससे भी त्वचा पर एक ग्लो बरकरार रहता है।

दही

दही में लैक्टिक एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वहीं, न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि लैक्टिक एसिड स्किन को सॉफ्ट और स्मूद बनाने में मदद करता है।

अमरूद या विटामिन सी से भरपूर फल

इन सब से अलग दीपशिखा जैन विटामिन सी से भरपूर फल खाने की सलाह देती हैं। 'विटामिन सी कोलेजन को बूस्ट करने में मदद करता है, जिससे भी स्किन पर ग्लो बरकरार रहता है और त्वचा हेल्दी बनी रहती है।' ■

तनाव दूर करता मेडिटेशन

छोटे बच्चे स्वभाव से बेहद मासूम होते हैं और अधिक भावुक होने के कारण वह किसी भी बात को बेहद जल्द अपने दिल से लगा लेते हैं। लेकिन जो बच्चे नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, वह अपनी भावनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण करने में सक्षम हो जाते हैं।

मेडिटेशन से होने वाले फायदे किसी से छिपे नहीं हैं। आज के समय में जब हर व्यक्ति किसी न किसी तरह के तनाव से जूझ रहा है तो मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास बेहद फायदेमंद होता है। वैसे यह सिर्फ व्यस्क के लिए ही लाभदायक नहीं है, बल्कि इससे बच्चों को भी उतना ही फायदा होता है। तो चलिए जानते हैं मेडिटेशन से बच्चों को होने वाले कुछ लाभों के बारे में–

तनाव में कमी

मेडिटेशन का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह तनाव कम करने में बेहद प्रभावी है। चूंकि आज के समय में बच्चे पढ़ाई व अन्य कई एक्टिविटी में अच्छा परफार्म करने के मानसिक दबाव में होते हैं। कई बार पीयर प्रेशर भी उनके तनाव का कारण बनता है। इस प्रकार अगर वह मेडिटेशन करते हैं तो इससे तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है।

बेहतर विकास

बच्चों के बेहतर विकास में मेडिटेशन एक अहम भूमिका निभा सकता है। इससे मन तो रिलैक्स होता है ही, साथ ही इससे बच्चे की मेमोरी व एकाग्रता दोनों बेहतर होती है। जिससे बच्चे पढ़ाई से लेकर खेलकूद में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मानसिक रूप से स्थिर व शांत होने के कारण वह विपरीत परिस्थितियों में भी घबराते नहीं है और बेहतर निर्णय करते हैं। इस प्रकार उनके निर्णय करने की क्षमता में भी सुधार होता है।

भावनाओं पर नियंत्रण

छोटे बच्चे स्वभाव से बेहद मासूम होते हैं और अधिक भावुक होने के कारण वह किसी भी बात को बेहद जल्द अपने दिल से लगा लेते हैं। लेकिन जो बच्चे नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, वह अपनी भावनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण करने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसे बच्चे पहले स्थिति को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद ही रिएक्ट करते हैं। ऐसे बच्चे न तो छोटी–छोटी बातों पर जिद करते हैं और न ही हर बात पर गुस्सा।

अधिक आत्मविश्वासी

जब बच्चा मेडिटेशन करता है तो इससे उसका दिमागी विकास होता है। जिसके कारण बच्चे में आत्म जागरूकता व आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास होता है। जब एक बच्चा अधिक आत्मविश्वासी बनता है तो उसका सकारात्मक असर उसके हर क्षेत्र में दिखाई देता है। इसलिए यह बेहद आवश्यक है कि बच्चों को मेडिटेशन करने की आदत डाली जाए। हालांकि इसके लिए जबरदस्ती न करें, बल्कि उसे इसके फायदे बताएं ताकि वह खुद–ब–खुद मेडिटेशन करने के लिए प्रोत्साहित हो। ■

तेजस INSTITUTE OF PARAMEDICAL AND NATUROPATHY

LATERA, DUMARIYAGANJ, SIDDHARTH NAGAR (U.P.)

COURSES

BNYS, BYN, DNYS, D.PHARMA, GNM

CCH, CGO, CMS, DMLT, DYT, DDT

DDH, ECG

AND E-RAY TECHNICIAN

PRESS

तेजस बिन्दु न्यूज

साहस सत्य बयां करने का